

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

31 मार्च, 1982

खण्ड 1, अंक 14

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 31 मार्च, 1982

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(14)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(14)18
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(14)28
वाक आउट	(14)39
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(14)39
ध्यानाकर्षक सूचना:—	
जिला महेन्द्रगढ़ तथा जिला रोहतक की कोसली तहसील के बहुत ज्यादा पिछड़ेपन तथा गरीबी की हालत होने सम्बन्धी	(14)43
वक्तव्य:—	
1. खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा राज्य में सीमेंट, चीनी, मिट्टी का तेल व कुकिंग गैस का वितरण सामान्य न होने सम्बन्धी।	(14)44

2. आबकारी तथा कराधान मंत्री द्वारा राज्य में बन्धक मजदूरों सम्बन्धी।	(14)50
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट	(14)55
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(14)65
बिल्ज:-	
1. दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 3) बिल, 1982	(14)66
2. दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 2) बिल, 1982	(14)70
3. दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 1) बिल, 1982	(14)72
अनैक चर	(14)74

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 31 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Loans to the Small and Marginal Farmers under Drought Prone Area Programme

***2593. Sh. Inderjit Singh:** Will the Minister for Agriculture pleased to state:-

(a) the district wise number of application received for loan from the Small and Marginal Farmers of the State during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 (to-date) under Drought Prone Area Programme in the State;

(b) the number of persons, out of those referred to in part(a) above, who have received loan;

(c) the district wise number of beneficiaries who received subsidy, if any, under the Drought Prone Area Programme during the years mentioned at (a) above; and

(d) whether the Government have received any complaint about the non-cooperation of the Nationalised Banks in the matter of advancing loans to the Small and Marginal Farmers?

Agriculture Minister (Sh. Shamsheer Singh):

(a), (b) and (c); A statement is laid on the Table of the House.

(d) While there have been stray cases of delay in the sanction and disbursement of loans, the Nationalised Banks by and large have co-operated well with the Agencies in the matter of advancing loans to Small and Marginal Farmers.

Statement

Sr.	Name of DPAP Distt.	(a) The District wise No. of application received from small and marginal farmers of the State during years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 (to date) under DPAP in the State			(b) The number of persons out of those referred to in part (a) who have received loan			(c) The District wise No. of beneficiaries who received subsidy, if any, under DPAP during the years mentioned in part(a)		
		1979-80	80-81	81-82	1979-80	80-81	81-82	1979-80	80-81	81-82
1	Rohtak	3080	2160	Nil	2767	1523	Nil	2767	1523	Nil

2	Bhiwani	2957	2371	138	2150	1731	9	2011	1731	9
3	Mohindergarh	33474	8915	Nil	2020	2461	Nil	1930	2388	Nil
	Total	9384	13446	138	6937	5715	9	6708	5642	9

श्री इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 1981-82 के अन्दर रोहतक और महेन्द्रगढ़ जिलों में किसी भी फारमर को सबसिडी नहीं मिली। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री भाम ोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, डी.पी.ए. का प्रोग्राम 1974 में लागू हुआ और उसके बाद 2-10-1980 से हरियाणा के सभी ब्लॉकस आई.आर.डी.पी. के नीचे कवर हो गए। इसके अनुसार इंडिविजुअल बैनिफि ग्यरी बेस्ड स्कीम तो आई.आर.डी.पी. को चली गई और जो लैंड बेस्ड स्कीम थी वह डी.पी.ए.पी. को चली गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। पहले डी.पी.ए.पी. तमाम एरियाज में इंडिविजुअल लोन लेने की स्कीम तथा लैंड बैस्ड स्कीम्ज जैसे ऐफौरस्टे गन और दूसरी स्कीम्ज को कवर करता था लेकिन 2-10-1980 के बाद इंडिविजुअल बैनिफि ग्यरी स्कीम तो आई.आर.डी.पी. को चली गई और लैंड बैस्ड स्कीम्ज डी.पी.ए.पी. को चली गई। दोनों में काम को डिस्ट्रीब्यूट हो गया।

राव बंसी सिंह: स्पीकर साहब, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि महेन्द्रगढ़ जिले में 1980-81 में 8915 ऐप्लीके ांज आई और लोन केवल 2461 ऐप्लीकेन्ट्स को दिया गया। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि ज्यादा लोगों को लोन क्यों नहीं मिला ?

श्री भाम ाेर सिंह: स्पीकर साहब, यह वह पीरियड है जब यह चेंज ओवर हुई है। हो सकता है कि कुछ ऐप्लीके ांज आई.आर.डी.पी. को चली गई हो और कुछ डी.पी.ए.पी. को चली गई हो। यही कारण हो सकता है।

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि आई.आर.डी.पी. के थ्रू लोन दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि झोटा बुग्गी खरीदने के लिए जो किसानों को लोन दिया जाता है वह कै ा में दिया जाता है या उनको झोटा बुग्गी खरीद कर दी जाती है ?

श्री भाम ाेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आई.आर.डी.पी. स्कीम के तहत हर ब्लॉक में छः सौ परिवार पर ईयर कवर किए जाते हैं। गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए बैंक लोन देते हैं और सरकार सबसिडी देती है। ऐग्रीकल्चर के लिए या दूसरी स्कीम्ज के लिए अथवा िड्यूल्ड कास्टस या दूसरे आर्टिजंज को नकद पैसा देने की बजाय चीज खरीद कर देते हैं। क्योंकि अगर नकद दें तो मिसयूज होने का डर है।

सरकार स्माल फार्मर्ज को 25 परसैन्ट और आर्जनल फार्मर्ज को 33 परसैन्ट सबसिडी हर लोन पर देती है ।

सरदार सुखदेव सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कहीं लोन कम मिलने का कारण यह तो नहीं है कि बैंक नै गलेलाइज्ड हैं और हमारी स्टेट का उन पर सीधा कंट्रोल नहीं है । जैसे किसी ने झोटा बुग्गी खरीदनी है उसकी रसीद के बारे में वे लोगों को तंग करते हों और कहते हां कि पहले रसीद लाओ तब पैसा मिलेगा, इस तरह से उनको हैरास करते हों ? क्या सरकार इस बारे में कोई टाईम फिक्स करेगी कि एक, दो या तीन महीने के अन्दर अन्दर अव य ही लोन मिल जाना चाहिए ?

श्री भामोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि बैंको पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं है । उनका अलग से बोर्ड बना हुआ है । जहां तक सरकार के इस प्रयत्न का ताल्लुक है कि निर्धारित समय में लोगों को लोन मिल जाना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमने ने गलेलाइज्ड बैंक, जिनकी ब्रांचिज हरियाणा में हैं, के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्ज की मीटिंग बुलाई थी । उस मीटिंग में मैं भी था । मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने उस मीटिंग को ऐड्रैस किया था । उस मीटिंग में लोन लेने के लिए जो किसानों की प्रोबलम्ज हैं उनको दूर करने के बारे में तथा रैड टेप को कट करने के बारे में थारो डिस्कान हुआ था और पूरे सुझाव दिए गए थे । उन्होंने वचन दिया था कि इस तरह का प्रबन्ध करेंगे कि लोन लेने में ज्यादा टाईम न लगे और जो

लोन लेने का प्रोसीजर है उसमें ज्यादा मुक्ति कल न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि आई.आर.डी.पी. का लोन लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बैंक में नहीं जाना पड़ता। प्रोग्राम यह है कि जिस एरिया में बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है वहां मौक पर ए.पी.ओ.ज. पहुंच जाते हैं और बेनीफि गायरीज से मौके पर दरखास्त लेकर उसको तसदीक करवा लेते हैं और मौके पर जलसा करके लोन के पेपर और चैक दे देते हैं। अगर लोग अन्धेरे में हों और वैसे ही चक्कर काटते रहें तो दूसरी बात है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को लोन लेने में कोई दिक्कत न हो।

चौधरी रिजक राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पार्ट डी के जवाब में बताया है कि ने नेनेलाइज्ड बैंकों की स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स को कर्जा देने के बारे में कुछ जानकारी देना है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितनी ऐप्लीकेशंस स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स की तरफ से ने नेनेलाइज्ड बैंक्स को आई और उनमें से कितनी रिजेक्ट हुई। दूसरी बात यह है कि अब जो लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। उनमें स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स की कितनी परसन्टेज को कवर करना है ?

श्री भामदेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी का पहला सवाल है कि कितनी दरखास्तें आई और कितनों को लोन दिया। मैं आनरेबल मैम्बर को बताना चाहता हूँ कि यह

सवाल डी.पी.ए.पी. का था, इसलिए ये फिगर्ज मेरे पास नहीं है। जहां तक दूसरे सवाल का संबंध है, कि आई.आर.डी.पी. के नीचे मार्जिनल और स्माल फार्मज कितने कवर किये हैं, इसके बारे में, मैंने पहले ही बताया है कि 2-10-1980 से यह प्रोग्राम चालू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत पहले साल 700 फ़ैमिलीज, दूसरे साल 1012 फ़ैमिलीज और तीसरे साल लगभग 1500 फ़ैमिलीज को कवर करने का प्रोग्राम है।

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के पार्ट डी के उत्तर में कहा है कि कर्जा की मन्जूरी व बांटने के कुछ मामलों में देरी हुई है, परन्तु कुल मिलाकर, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु एवं सीमान्त किसानों को कर्जे देने के मामले में एजेन्सियों को अच्छा सहयोग दिया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि आया उनके नोटिस में यह बात है कि सरकार की तरफ से जो सबसिडी लोनीज को मिलती है, उसमें से बैंक वाले 50 परसेन्ट या 25 परसेन्ट रि वत मांगते हैं ?

श्री भाम ोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ और न ही किसी को बलेंकड डिफेन्ड ही कर रहा हूँ। मैं आनरेबल मैम्बर साहेबान को यह बताना चाहता हूँ कि बैंक वाले सबसिडी नहीं देते हैं। बैंक तो केवल लोन ही एडवान्स करता है। फर्ज करो किसी ने भैंस खरीदने के लिए 3000 हजार रुपये का लोन लिया, बैंक तो कर्जा दे देता है और लोनी भैंस खरीद लेता है। उसके बाद आई.आर.

डी.पी. वाले फार्मर्ज की तरफ से एक हजार रूपया जमा करवा दैते हैं और फार्मर्ज को केवल दो हजार रूपया ही वापिस देना पड़ता है। जिस पर चार परसैन्ट इंटरैस्ट लगता है। यानी वन थर्ड सबसिडी के रूप में आ जाता है और टू थर्ड फार्मर को देना पड़ता है। इसलिए बैंक तो ऐसे किसी काम में पिक्चर में ही नहीं आता तो उसके खाने पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रोहतक और महेन्द्रगढ में फार्मर्ज को जो सबसिडी दी जाती है, वह बिल्कुल जीरो परसैन्ट के बराबर ही है, ऐसा क्यों है ? करनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है ? सरकार इस तरह की भेदभाव की नीति क्यों अपना रही है ?

श्री भाम ोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने हिबना पढ़े और बिना सोचे ही यहां पर इस तरह का सवाल पूछ लिया। रोहतक में सबसिडी निल नहीं है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि डी.पी.ए.पी. से यह प्रोग्राम आई.आर.डी.पी. में चला गया है।

Per capita quantity of Sugar Distribution in Rural & Urban Areas

***2606. Ch. Sant Kanwar:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) the per capita quota of sugar being distributed at present per month in the rural and urban areas of Haryana, separately;

(b) the number of ration cards which stand issued in district Rohtak at present; and

(c) the total quantity of sugar allocated every month for district Rohtak during the year 1981-82 (todate) ?

Food and Supplies Minister (Sh. Lachhman Singh):

(a) Government have fixed the quantum per capita of levy sugar per month at 400 grams. However, the Deputy Commissioners make local adjustments in the scale of issue, where ever necessary, according to requirements due to lesser allocation of sugar by Govt. of India.

(b) 203046.

(c)

Month	Quantity of Sugar Allotted (in tonnes)
April, 81	510
May, 81	510
June, 81	510
July, 81	510

August, 81	510
September, 81	506
October, 81	526
November, 81	236
December, 81	506
January, 82	506
February, 82	506
March, 82	489
Total	6125 Tonnes

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जबाव में बताया कि रोहतक जिला में 203046 रा 1न कार्डज है। इसके हिसाब से चीनी का वितरण किया जाता है। हर व्यक्ति को हर महीने 300 ग्राम चीनी मिलनी चाहिए लेकिन वह पूरी नहीं मिलती है। क्या यह बात सच नहीं है कि सिवाय एक आध महीना छोड़ कर तीन सौ ग्राम की बजाये लोगों को 200 व 225 ग्राम चीनी दी जाती है। इसके क्या कारण है ? क्या सरकार ने कभी इस तरह की जांच करवाने का विचार किया है कि बीच की चीनी कौन खा जाता है ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, रोहतक का हमारे पास रिकार्ड है। देहात में 300 ग्राम और भाहरों में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी दी जाती है लेकिन जैसा कि आनरेबल मैम्बर श्री संत कंवर ने बताया कि लोगों को 200 या 25 ग्राम चीनी मिलती है, इस तरह की बात हमारे नोटिस में कोई नहीं आई। अगर माननीय सदस्य हमें ऐसा कोई वाक्या बताएंगे तो हम अब य एक ान लेंगे।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, डिपोज पर एक महीना चीनी लेट मिलती है और जब अगले महीने मिलती है तो 29 और 30 तारीख के लगभग मिलती है। क्या इस गलती को सरकार सुधारने का प्रयत्न करेगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इस तरह की ि ाकायतें मिली थी। इसके कई कारण हैं, सबसे पहले तो होल सेलर्ज हैं, उन से चीनी लेट मिलती है। दूसरा अब यह रा ा का सारा काम हैफड के सुपुर्द कर दिया गया है, वहां से उठाने में भी हो सकात है कि देरी हो जाती हो। अब हमने यह आर्डर कर दिया है कि हर महीने की 15 तारीख तक लोगों को चीनी का वितरण अब य हो जाना चाहिए। इस तरह की हिदायतें हमने केवल रोहतक के लिए ही नहीं की बल्कि ऐसी हिदायते जनरल तौर पर सारे हरियाणा के लिए ही कर दी गयी है। अब हर महीने लोगों को ठीक समय पर चीनी मिल जाया करेगी। वैसे स्पीकर साहब,

देरी के कुछ कारण तो मैंने बताए, एक दो कारण ओर भी हैं कि जैसे किसी का डिपो किसी कारण से कैंसिल हो गया तो उस हल्के के लोगों को इसी वजह से चीनी लेट मिलती है या किसी डीलर ने खुद ही माल लेट उठाया। कई बार हैफड वाले भी देरी कर देते हैं क्योंकि उनके पास राशन कार्ड की कई आइटमज हैं अकेली चीनी ही उनके पास नहीं होती है।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मेरा पहला सप्लीमेंटरी यह है कि जितनी चीनी सैन्टर से स्टेट को कोर्ट के मुताबिक मिलनी चाहिए थी, वह मिली है कि नहीं ? दूसरी सप्लीमेंटरी मेरी यह है कि रोहतक जिला के गांवों के लोगों को होली के त्यौहार पर चीनी नहीं दी गई और लोगों ने होली का त्यौहार नहीं मनाया। इस बारे में मैंने डी.सी. साहब को, डी.एफ. सी. साहब को और साथ ही मिनिस्टर साहब को भी बताया था कि इस तरह का गांवों के लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बी.डी.ओ. और डी.एफ.सी. साहब ने लोगों के राशन कार्ड अपने कब्जे में कर लिये और यह कहा कि चूल्हा टैक्स दे जाओ, तब कार्ड मिलेगा। किसी गरीब आदमी को अभी तक राशन कार्ड वापिस नहीं किए गये हैं। क्या यह बात सरकार के नोटिस में है, क्या ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, कई बार अखबारों में भी यह आ चुका है कि हमें 700 टन चीनी सैन्टर से कम मिली

है। हम इस बारे में भारत सरकार से कोर्िया में लगे हुए हैं और हमें आता है कि इसका जल्द ही फैसला हो जाएगा। इसीलिए अभी तक हमने 400 ग्राम चीनी के पैट्रन को नहीं बदला है। जहां तक चूल्हा टैक्स का ताल्लुक है, इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब मुझे दलाल साहब ने इस बारे में बताया था तो उसी वक्त मैंने डी०सी० और डी०एफ०सी० साहब को कह दिया था और हिदायतें जारी कर दी थी कि चूल्हा टैक्स लेना हमारी डियूटी में नहीं आता। ऐसी रिक्कायत केवल रोहतक जिले में ही थी और स्टेट में कहीं नहीं थी। अब इस समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और न ही कोई चूल्हा टैक्स लिया जा रहा है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि गांवों में 400 ग्राम चीनी पर व्यक्ति के हिसाब से नहीं मिल रही है। इस बारे में हमने भारत सरकार से बातचीत की है और इस बात का फैसला कर दिया है कि अप्रैल के महीने से चाहे देहात हो, चाहे भाहर हों, सभी जगहों पर 400 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से एकसां चीनी का वितरण किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कल एक मंत्री महोदय ने यहां पर स्टेटमेंट दी थी कि जो किसान अपना गन्ना फ़ैक्टिरियों में देंगे, उनको चीनी का कोटा दिया जाएगा क्या वह कोटा भी इससे संबंधित है ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, वह तो गन्ने के इवज में है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, क्या यह सरकार के नोटिस में है कि जब डिपो होल्डर चीनी लेने जाता है तो जो परमिट उसको काट कर दिया जात है, उस परमिट पर बोरी के हिसाब से पैसे बन्धे हुए हैं ? जैसाकि मेरे भाई चौधरी संत कंवर जी ने बताया कि देहातों में गरीब लोगों को 300 ग्राम चीनी की बजाये अढ़ाई सौ या सवा सौ दो सौ ग्राम चीनी दी जाती है ओर कार्डों पर 300 ग्राम चीनी ही चढ़ाई जाती है। जो चीनी में कट लगाई जाती है, वह इस वजह से तो नहीं हैं क्योंकि डिपो होल्डर से पर बोरी पैसे चार्ज ज्यादा दिये जाते है। जब डिपो होल्डर से इस बारे में बात की जाती है तो वे कहते हैं कि हमारे से पर बोरी के हिसाब से पैसे लिये जाते हैं तो हम ये पैसे कहां से भरे। क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी और इस बात की जांच भी करवायेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री लछमन सिंह: इस बारे में न कभी मुझे बूरा साहब ने बताया है और न संत कंवर जी ने बताया है। मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं गवर्नमेंट से दख्तास्त करूंगा कि वह इस बारे में स्पै 1 ल रेडज और चैकस करवाएं।

श्री लछमन सिंह: वह तो हम पहले ही करवाते हैं।

चौधरी अजीत सिंह: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रोहतक जिले में जिन लोगों को पिछले महीने की चीनी नहीं मिली क्या उनको अगले महीने इकट्ठी दो महीने की चीनी दी जाएगी ?

श्री लछमन सिंह: उनको चीनी जरूर मिल जाएगी। मैम्बर साहब मुझे गांवों के नाम बता दे, उनको पिछले महीने का कोटा भी अगले महीने में दे दिया जाएगा। मैं आज ही हिदायत जारी कर दूंगा।

श्री भले राम: अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि अप्रैल के महीने से भाहर और गांव में हर व्यक्ति को 400 ग्राम चीनी दी जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 400 ग्राम चीनी जून तक ही मिलेगी या आगे भी मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष: मैं तो समझ रहा था कि आप मुख्य मंत्री जी को बधाई देंगे। (हंसी)

चौधरी जय नारायण: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ब्याह भाादियों के लिए गरीब, मजदूर और किसानों को एक दो बोरी चीनी कन्ट्रोल रेट पर देने का विचार करेंगे ?

श्री लछमन सिंह: ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है। चीनी तो बाजार में आम मिलती है। एक भारत ही ऐसा दे ा है जहां रा ान कार्ड पर 3.65 रु. प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जाती है वरना कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है।

चौधरी गया लाल: क्या मंत्री जी का जानकारी में यह बात है कि बहुत से डिपो होल्डर इन्सपैक्टर से मिल कर महीने के आखिरी टाइम यानी 29-30 तारीख को चीनी उठाते हैं और उसे दूसरे महीने में बांटते है। क्या मंत्री जी कोई हिदायत जारी करेंगे कि महीने की चीनी फलां तारीख तक डिपो पर पहुंच जानी चाहिए ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, हमने पहले ही डेट फिक्स की हुई है कि हर डिपो पर 15 तारीख तक चीनी पहुंच जानी चाहिए। लेकिन किसी वजह से अगर थोड़ी लेट हो जाए तो उसके कई कारण होते हैं जो मैं पहले बता चुका हूं। यह कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी को एक महीने की चीनी नहीं मिलेगी तो वह दूसरे महीने जरूर मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: जब गया लाल जी बोल रहे थे तो दोनों साइड के मैम्बर साहेबान और कुछ मंत्रीगण भी इस बारे में एजीटेटिड फिल कर रहे थे। मैं गवर्नमेंट से रिकवैस्ट करूंगा कि इस पर वह स्ट्रिक्टली चैकस एंड बेलेंस रखे।

श्री लछमन सिंह: वह हम कर रहे है जी।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि जिस गांव में किसी महीने की चीनी नहीं जाती है जैसे फर्ज करो मार्च के महीने की चीनी किसी डिपो होल्डर ने नहीं उठाई तो अप्रैल के महीने में दोनों की चीनी दी

जाएगी ताकि पिछले और चालू महीने यानी दोनों महीनों की चीनी लोगों को दी जाए। इस मामले में किसी गांव के साथ भी भेदभाव नहीं बरता जाएगा।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बहुत फूल प्रूफ है। वहां पर सरपंच के दस्तखत होते हैं, हरिजन पंच, हैड मास्टर और पटवारी के भी दस्तखत होते हैं। तो चार आदमियों का सर्टिफिकेट होता है। उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो हम एम.एल.ए. के भी दस्तखत करवाने को तैयार हैं।

श्री देवी दास: अभी मंत्री जी ने बताया कि जब सेंटर से चीनी का कोटा कम आता है तो डी.सी. साहेबान उसको एडजस्ट करके कोटा कम दे सकते हैं। क्या साल में कोई ऐसा महीना भी आया है जब 100 या 200 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी किसी जिले में दी गई हो ?

श्री लछमन सिंह: ऐसा कोई केस नहीं हुआ है।

श्री बलदेव तायल: क्या मंत्री महोदय हिन्दुस्तान में इकोनोमिक डिसपैरिटी को देखते हुए कोई ऐसी पालिसी बनाएंगे कि इतनी इंकम से ऊपर के जो लोग हैं उनको राशन की चीनी नहीं मिलेगी और जो गरीब लोग हैं केवल उन्हीं को मिलेगी ?

श्री लछमन सिंह: ऐसा कोई विचार नहीं है।

स्वामी अग्निवे : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर पांच लाख से भी अधिक मजदूर काम करने के लिए बाहर के प्रान्तों से आते हैं और वे 8-9 महीने प्रान्त में काम करते हैं। उनका कोई राशन कार्ड नहीं होता, वे सबसे ज्यादा एक्सप्लायटड होते हैं क्या सरकार ऐसी स्कीम बनाएगी कि जितने दिन वे हरियाणा में सेवा करते हैं उतने दिन के लिए उनके राशन कार्ड बना दिये जाएं ?

श्री अध्यक्ष: प्वायंट यह है कि माइग्रेटिड लेबर को राशन कार्ड बनाने का अधिकार है या नहीं ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, हम माइग्रेटिड लेबर के लिए तीन महीने के लिए राशन कार्ड बनाते हैं। उसके बाद अगर वह यहां सैटल हो जाता है तो अपना राशन कार्ड रिन्यू करवा सकता है। इस बारे में जैन साहब ने भी मुझे चिट्ठी लिखी थी तो मैंने उनको जवाब दिया था अगर कोई ऐसे केसिज हैं तो उनको मेरे पास भेजिये, हम बनवा देंगे

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे पहले भाादियों के लिए कन्ट्रोल रेट पर चीनी दी जाती थी क्या अब भी सरकार देने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब पहले ही जा चुका है।

चौधरी संत कंवर: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने मेरे और बूरा साहब के सवाल के जवाब में बताया कि गांवों में 300 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी गई है। मंत्री जी चार आदमियों की एक कमेटी बनाएं और मेरे साथ रोहतक जिले में भेजें तो मैं साबित कर दूंगा कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी के अन्दर हर गांव में दो सौ ग्राम से ऊपर चीनी नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष: हर बात के लिए कमेटी नहीं बन सकती। आप मंत्री महोदय की इस बारे में योर करने के बारे में कह सकते हैं। अभी मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया है कि अप्रैल के महीने से सब जगह 400 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी मिलेगी।

Pension benefits to Provincialised Doctors

***2630.@Sh. Fateh Chand Vij, Sh. Baldev Tayal:**

Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) whether the pensionary benefits have been allowed to the doctors of the provincialised Hospitals/dispensaries which were taken over by the Government;

(b) if so, the total number of doctors, as referred to in part (a) above, who became entitled to such pensionary benefits;

(c) the total number of doctors, out of those referred to in part (b) above, who applied for pension and the number out of those whose pensions have been sanctioned and are being disbursed to them;

(d) whether there are any doctors, out of those referred to in part (b) above, who have not been sanctioned pensions because their service books are not available and are missing as such have not been sanctioned so far;

(e) whether the Government proposes to grant pension to such doctors after obtaining their affidavits and production of indemnity bonds to avoid harassment to them; and

(f) in the alternative whether there is any proposal under consideration of the Government to disburse 75% of their pension to the doctors, referred to in part (d) above, pending disbursement of full pension subsequently?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मन्त्री (चौधरी गजराज बहादुर):

(ए) हां

(बी) ठीक संख्या उपलब्ध हैं ।

(सी) (1) 18 तथा) भून्य ।

(डी) हां, 9

(इ) हां ।

(एफ) नहीं ।

श्री फतेह चन्द विज : मन्त्री महोदय ने सवाल के पार्ट (ए) का जवाब दिया है कि 'हां' लेकिन इन्होंने टाइम नहीं बताया। 25 साल हो गए हैं क्या अभी तक इनके पास ठीक संख्या उपलब्ध नहीं हुई है कि कौन कौन से डाक्टर पैन्शन के हकदार हैं। आगे इन्होंने बताया है कि डाक्टरों ने पैन्शन के एप्लाइ किया है और उनमें से 9 डाक्टरों की सर्विस बुकस नहीं मिलीं हैं जिस वजह से उनको पैन्शन नहीं दी गई। बाकी 9 डाक्टरों के बारे में भी पता नहीं कि उनको पैन्शन दी है या नहीं। जिन डाक्टरों की सर्विस बुक गुम हैं उनसे ये एफीडेविट लेकर फैसले के मुताबिक 75 प्रतिशत पैन्शन दे देंगे। मैं अपनी सप्लीमेंटरी एक भोर के जरिए पूछना चाहता हूँ -

मुसाफिर जब कोई जंगल में भटक कर मर गया

फिर कोई सदा देते हुए कारवां आया तो क्या।

श्री अध्यक्ष : अगर आप इस भोर का भी नोटिस दे देते तो आपको भोर में ही जवाब मिल जाता है।

10.00 बजे

चौधरी गजराज बहादुर नागर : स्पीकर साहब, मैं फाजिल मैम्बर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि जो जिला परिषद् और लोकल बाडीज के होस्पिटल हैं या दूसरी बाडीज के होस्पिटल हैं उनके डाक्टरों की सर्विस पैन्शनरी बेंनीफिट देने के लिए प्रोविन्सियलाइज्ड की गई थीं। इनको पहले

पैन् इनकी बैनीफिट देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इस समय जो निर्णय लिया गया है उसमें उनको दो बैनीफिट होंगे। एक पैन् इन का बैनीफिट होगा दूसरा पी0एफ0 का बैनीफिट होगा। पहले किसी भी सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया कि प्रोविन्सलाइज्ड डाक्टरों को पैन् इन का बैनीफिट दे दिया जाए। लेकिन यह चौधरी भजन लाल जी की सरकार है जिसने 14-1-82 को यह निर्णय लिया है कि प्रोविन्सलाइज्ड डाक्टरों को पैन् इन का बैनीफिट दे दिया जाए। 14-1-82 के निर्णय के बाद ऐसे 18 कैसिज पैन् इन के ए0जी0 आफिस में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा हमने यह पब्लिसिटी भी करा दी है कि यदि किसी डाक्टर की सर्विस प्रोविन्सलाइज्ड की गई है और वह पैन् इन का हकदार है तो वह एप्लाई करे। यदि किसी की सर्विस बुक नहीं मिल रही है तो वह एफीडैविट देकर हमारे पास एप्लाई कर सकता है।

डा० बृज मोहन गुप्ता : स्पीकर साहब, जिन डाक्टरों की सर्विस प्रोविन्सलाइज्ड की गई थी, यदि डेथ हो चुकी है और उनके बच्चे या बीवी पैन् इन के लिए एप्लाई करते हैं और कहते कि हम पैन् इन के हकदार हैं तथा हमारी इतनी पैन् इन डय हैं। वह पैन् इन के लिए एफीडैविट भी दे दे तो मैं मंत्री जी से यह चाहता हूँ कि क्या सरकार उनको पैन् इन देने के लिए तैयार है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर : स्पीकर साहब, पैन् इन का बैनीफिट देने के लिए जिस पैटर्न पर एजूके इन ने सिस्टम

एडाप्ट किया हैं उसी प्रकार से हैल्थ डिवाटमेंट एडाज्ट करेगा।
यदि रूल्ज में ऐसा प्रोविजन होगा तो अव य कंसीडर करेंगे।

श्री बलदेव तायल : स्पींकर साहब, मंत्री जी ने सवाल के पार्ट 'ख' का जवाब दिया हैं कि ठीक संख्या उपलब्ध नहीं हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनको फिगर बताने में क्या कठिनाई हैं ? ये सहीं फिगर क्यों नहीं बता पाते ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर : स्पींकर साहब, मैं यह पहले हीं अर्ज कर चुका हूं कि इस बारे में 14-1-82 को निर्णय लिया गया है और हम इस इंतजार में हैं कि जो कलेंमैटस हमारे पास आएंगे वे अपना एफींडैविट देंगे कि हम पैन् इन के हकदार हैं उनको पैन् इन देने के लिए कंसिडर किया जाएगा। हमने ऐसे 18 केसिज ए0 जी0 आफिस में भेज दिए हैं। यदि आज मैं यह कह दूं कि उनकी संख्या 20 हैं और कल को उनकी संख्या 30 हो जाती है तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी।

Duplicate Roads

***2635. Ch. Ude Singh Datal :** Will the Minister for Public works (B & R) please state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal those duplicate roads, if any, in the State on which earth work has already been done : and if so, the time by which metalling work is likely to be completed ?

लोक निर्माण मन्त्री (कंवर राम पाल सिंह) : जिन दोहरीं सड़कों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा मिट्टी का काम किया जा चुका है, वे सभी पक्कीं कर दी जायेंगी। परन्तु इस समय यह बताना संभव नहीं कि ऐसा कब तक तय कर दिया जाएगा।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आज से दो साल पहले मुख्य मंत्री जी ने हाउस में यह अनाउंसमेंट की थी कि जिला परिशद, मार्किट कमेंटी और ब्लाक समिति की जितनीं रोडज है, उनको पी०डब्ल्यू० डी० ने प्रोविन्सिलाइज्ड कर दिया है और उनकी मुरम्मत करवा दीं जाएगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के नोटिस में मुख्य मंत्री जी की वह बात है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि रोहतक में जिला परिशद, मार्किट कमेंटी और ब्लाक समिति की जितनी रोडज हैं वे सारी टूटी हुई हैं मुख्य मंत्री की अनाउंसमेंट के बाद भी उनकी मुरम्मत आज तक नहीं हुई है, उन रोडज की मुरम्मत कब तक करवा दीं जाएगी ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने हाउस में जो अनाउंसमेंट की थी उसके मुताबिक जिला परिशद, मार्किट कमेंटी और ब्लाक समितियों की रोडज पी० डब्ल्यू० डी० ने प्रोविन्सिलाइज्ड कर दीं हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों हमारे पास फण्डज आते जा रहे हैं, हम रोडज की मुरम्मत करते जा रहे हैं। रोडज की मुरम्मत करना फण्डज की अवेलेबिल्टी पर डिपेंड करता है चाहे कोई सड़क ब्लाक समिति की

हो, चाहे मार्किट कमेटी की हो। इस समय हमारे पास फण्डज अवेलेबल नहीं हैं।

श्री जय नारायण वर्मा : स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कुछ रोडज पर मिट्टी भी डल चुकी थी और ईटे भी आ चुकी थीं लेकिन वहां से ईटें उठा ली गई हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन रोडज पर मिट्टी डल चुकी है और ईटें भी डल चुकी हैं क्या उन रोडज की मुकम्मल करवाएंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने सवाल के जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन सड़कों पर लोक निर्माण विभाग ने मिट्टी डाल दी है उनको अब यही पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन समय के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है कि कितने समय के अन्दर रोडज को पक्का कर दिया जाएगा। यह फण्डज की अवेलेबिल्टी पर डिपेंड करता है।

कामरेड भांकर लाल : स्पीकर साहब, मेन रोड से जो लिंक रोडज बने हैं वे कई जगहों पर मुकम्मल नहीं बने हैं। इसके अलावा कई ऐसे गांव हैं जहां डबल रोडज की आवयकता है। मैं आपको सिरसा जिले के कुछ गांवों के नाम बताना चाहता हूं जिनमें डबल लिंक रोडज की आवयकता है। सिरसा जिले में एक लिंक रोड फुलका से कंवरपुरा तक बनाने की आवयकता है क्योंकि जो पहले रोड बना हुआ है, उस रोड से इन गांवों के आदमियों की 10 किलोमीटर का फासला तय करके आना जाना

पड़ता है जबकि इन गांवों का फासला सिर्फ दो किलोमीटर का है। इसी तरह से भरोंका से सुवाना और दड़बी से जोदां लिंक रोड बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इन गांवों के आदमियों को भी काफी फासला तय करके एक दूसरे गांव में आना जाना पड़ता है। इसके अलावा नेजा डेला से क्राडा लिंक रोड बनना चाहिए और केलीराना से अहमदपुर तक का लिंक रोड बनना चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस समय इन गांवों के लोगों को बहुत ज्यादा फासला तय करके एक दूसरे गांव में आना पड़ता है। किसी गांव का फासला 10 किलोमीटर का है और किसी का 8 किलोमीटर का है। ये सारे गांव मेरे हल्के में हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन गांवों के छोटे-छोटे, दो-दो किलोमीटर के लिंक रोड बनाए जाएंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : सरकार पहले से ही इन सब बातों का ध्यान रख कर अपना काम कर रही है कि यदि किसी गांव में छोटी सी सड़क बनाने से फासला कम हो सकता है तो उसकी पहले बनाया जाये।

चौधरी ई वर सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूँ कि दोहरे लिंक रोड बनाने का क्या क्राईटेरिया है ? दूसरा यह है कि यदि किसी गांव के लोग सड़क पर मिट्टी डाल दें तो क्या उन सड़कों को बनाने में सरकार प्रासुरिटी देगी ?

कंवर राम पाल सिंह : मैंने हाउस से पहले भी बताया है कि सरकार ने पहले ही काफी सिंगल रोडज बना दिए हैं सिवाए 173 सड़कों के। अब बजट प्लान के मुताबिक सड़कों का जो काम किया जाना है वह दोहरे लिंक रोडज का करना है। मैंने पहले भी बताया है कि यदि किसी सड़क के जोड़ने से हैड क्वार्टर, तहसील या ब्लाक नजदीक पड़ेगा तो उसको पहले बनाया जाएगा। (गोर) जहां तक क्राईरियों की बात है उसमें यह देखा जाता है कि डबल लिंक बनाने से कितना फासला कम हो सकता है बजट में कितना पैसा है और सड़क की कितनी लम्बाई है इन सब बातों को ध्यान में रखकर दोहरे लिंक रोडज बनाते हैं। जहां तक इनका दूसरा सवाल है कि यदि गांव के लोग मिट्टी डाले दें तो क्या वहां पर सरकार सड़क बना देगी। इस संबंध में ही अपने दोस्त को बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है और न ही यह मामला विचाराधीन है। यह बात जरूर है कि ऐसी सड़कें जहां पर मिट्टी डाल दी गई हो उन्हें पहले बनाया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सड़कें सरकार की तरफ से बनने के लिए 2-3 साल पहले पास हो गई थीं, क्या उनको बनाये जाने के लिए प्राथमिकता देंगे। क्योंकि भिवानी जिले में कोई काम नहीं हुआ है इस लिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी सड़कों को बनाने की कोशिश करेंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, अब हमारा सबसे पहला काम यह है कि जिन गांवों की आबादी 150 और 250 के बीच में हैं और वहां पर सड़कें नहीं हैं, वहां पहले बनाने की परपोजल हैं। (गोर)

डा० मंगल सैन : स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया है कि विभाग ने जिन सड़कों को बनाये जाने के लिए मिट्टी डाल दी है, उनका काम पूरा कर देगे। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि 6 महीने में पूरा कर देंगे, एक साल में पूरा कर देगे या इस प्लान में पूरा कर देगे या दूसरे प्लान में पूरा कर देंगे। इन्हें कोई समय तो बताना चाहिए कि इतने समय के अन्दर-अन्दर सड़क बना दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जहां पर विभाग ने मिट्टी डाल दी है वहां पर सड़क पहले बनाई जायें क्योंकि मिट्टी डालने के बाद जब बारिश हो जाती है तो वह सारी मिट्टी बह जाती है।

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कहा है कि जिन सड़कों पर विभाग की तरफ से मिट्टी डाल दी गई है, उनको पहले बनाया जाएगा। विभाग को भी इस बात का पता है कि यदि उनको नहीं बनाया जाएगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। मैं फिर भी कहता हूं कि ऐसी सड़कों को बनाने के लिए हम प्रायोरिटी देंगे। इस समय विभाग ने लगभग एक हजार

किलोमीटर लम्बाई की सड़कों पर काम भुरु किया हु आ हैं । इस काम को पूरा करने के लिए आज की कीमतों को ध्यान में रखते हुए 23 करोड़ की आव यकता हैं । यदि हमारे पास 23 करोड़ रूपया उपलब्ध हो जाये तो हम सारा काम एक साल में ही पूरा कर देंगे ।

श्री बलदेव तायल : स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे हल्के के साथ कोई भेदभाव नहीं किया क्योंकि आज तक कोई दोहरी सड़क नहीं बनाई गई हैं । लोगों की तरफ से मेरे पास कोई िाकायत नही आई कि फलां हल्के के अन्दर दोहरी सड़क बन गई हैं, फलां में नहीं बन रही । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये मेरे हल्के के अन्दर 100 मीटर, 10 गज या एक किलोमीटर दोहरी सड़क बनवा देंगे । यदि ये 5 गज या 10 गज भी दोहरी सड़क बनवा दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी । (गोर)

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, इस समय मेरे पास सूचना नहीं हैं कि इनके हल्के में कितना काम हुआ हैं और कितना नहीं हुआ हैं । यदि ये पूछना चाहते है तो मैं इन्हें बाद में बता दूंगा ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : स्पीकर साहब, अभी कुछ दिन पहले मैं हांसी तहसील में उमरा गांव में गया था । वहां

पर मैं 5 किलोमीटर दोहरी सड़क मंजूर करके आया था। उस पर दो महीने के अन्दर अन्दर काम भुरू हो जाएगा।

Shri Baldev Tayal : He is misleading the House. He has sanctioned not a single meter of double road. (Interruptions) Let him name the road. (Interruptions) Sir, he is misleading the House. He should withdraw his statement or name the village where duplicate road is being constructed.

चौधरी भजन लाल : अभी एक हफता पहले मैं वहां होकर आया हूँ ।

श्री बलदेव तायल : आप यहां उस रोड का नाम बता दे आपने रोड को वाईडन करने की बात की है। आप जब कभी पहले दौरे पर गए थे तब आपने इस काम को करवाने का वायदा किया था। चूंकि वह काम हुआ नहीं था इसीलिए अब आपने दुबारा वायदा किया है ।

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ) : स्पीकर साहब, वहां डुप्लीकेट लिंक बन रहा है। (गोर)

Shri Baldev Tayal : There is no duplicate road. I object to his replying to my question. Shri Jagan Nath is not the Minister concerned. He has no business to reply (Interruptions). He is speaking without your permission, Sir.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, हमें आपकी प्रोटैकान चाहिए। उनको इस तरह से बीच में बोलने से आप रोकें। यह कोई तरीका नहीं है।

Mr. Speaker : According to the rules any Minister can reply. If anything is within his knowledge and he wishes to reply on behalf of the Public Works Minister, I have no objection.

श्री मूल चन्द जैन : अफसोस की बात तो यह कि वे आपकी इजाजत के बगैर खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष : इजाजत के बगैर तो कई मेरे दोस्त आपकी तरफ से भी खड़े होते हैं और इधर से भी खड़े हो जाते हैं।

श्री मूल चन्द जैन : आप कृपया किसी मैम्बर का मिनिस्टर से तो मुकाबला न करें।

श्री बलदेव तायल : स्पीकर साहब, सोचने की बात तो यह है कि क्या एक ही सवाल का जवाब, मुख्य मंत्री जी भी देंगे, पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर भी देंगे और श्री जगन नाथ जी भी देंगे ? (विघ्न)

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, श्री बलदेव तायल की कांस्टीच्यूएन्सी हांसी है। हांसी में एक गांव है उमरा। उमरा से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर गांव है। सुल्तानपुर से

वहां को एक सड़क जाती हैं । फिर एक गांव है क्वारी। वह मेरे हल्के में है। उमरा से उस साईट को भी एक सड़क जाती है। (विधन) अगर इनको भाक हैं तो अभी एस0 डी0 ओ0 और एक्सीयन ने इन्फर्मे इन मंगवाई जा सकती हैं । यह इस बात को नहीं कह सकते कि वहां डुप्लीकेट लिंक नहीं हैं ।

श्री बलदेव तायल : स्पीकर साहब, मैंने डुप्लीकेट रोड की बात की हैं, डुप्लीकेट लिंक की बात नहीं की है। ये इसको कंप्यूज कर रहे हैं।

राव राम नारायण : स्पीकर साहब, मेरे हल्के में दस सड़कें ऐसी हैं वे अगर बन जाएं तो लोगों को तहसील हैडक्वार्टर और ब्लाक हैडक्वार्टर तक जाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर तक का सफर कम हो जाता है । इन सड़कों के बारे में मैं तीन दफा मिनिस्टर साहब को कह चुका हूं कि मुख्य मुत्री जी ने इन्हें बनवाने के लिए अ योरेंस दी हुई हैं । इस बार जब मंत्री जी से इस बारे में मैंने सवाल किया तो जवाब यह आया कि अभी इनको बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि इन्हें ये कब तक बनाएंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : अगर मुख्य मंत्री जी ने इस सड़कों को बनवाने का एलान किया होगा तो अब य इन्हें मंजूर करके बनवाया जाएगा।

श्रीमती डा० कमला वर्मा : स्पीकर साहब, कुछ इन्टरडिस्ट्रिक्टस रोडज हैं जिन्हें जिलों के एकसीयन्ज बनाने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अम्बाला जिला में एक गांव जयपुर है और कु रूक्षेत्र जिले में एक गांव अल्हर है। इन दोनों को एक सड़क से जोड़ा जाना है लेकिन यह सड़क पिछले चार साल से नहीं बन रही है। क्या मंत्री जी ऐसी सड़कों को बनवाने के लिए भी कोई कदम उठाएंगे?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, इन्होंने खुद ही कहा है कि उन सड़कों को बनाने में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। उन कठिनाइयां को दूर करके ही महकमा ऐसी सड़कों को बना सकता है।

कंवर विजय पाल सिंह : स्पीकर साहब, माननीय गृह मंत्री जी ने 1968-69 में सोहना से बल्लभगढ़ वाया सिरथला एक सड़क बनवाई थी। वहां सिराला ड्रेन के ऊपर सिरथला गांव के पास एक पुल बनना था। उसके लिए गृह मंत्री जी ने भी कई बार प्रयत्न किए और मैं भी पांच साल से आग्रह करता आ रहा हूँ। ड्रेन के एक ओर हाई स्कूल है और दूसरी तरफ तीन चार गांव हैं। बरसात के दिनों में 50-100 बच्चे हाई स्कूल नहीं जा सकते। क्या मंत्री जी उस पुल को भीघ्र बनवाने की कृप्या करेंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, इसका मैं ऑफ हैन्ड कोई जवाब नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैं कहूंगा कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो पुल की बात कही है, लगता है कि वह बड़ा जरूरी ब्रिज है । इसीलिए बेहतर होगा अगर सरकार उसके ऊपर भीघता से काम करवाए ।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने बिल्कुल ठीक प्वायंट रेज किया है और पुल बनना बहुत जरूरी लगता है । मैं इन्हें आपके द्वारा वि वास दिलाता हूं कि तीन महीने के अन्दर उसका काम भुरु करवा दिया जाएगा ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, चौधरी मेंहर सिंह जी जब पब्लिक वर्कस मिनिस्टर थे तो चार साल पहले एक सड़क पर, जो संजय गांधी रोड के नाम से माहूर है, लोगों ने मिट्टी डाली थी । संजय गांधी भी वहां तारीफ लाए थे और उन्होंने भी मिट्टी डालने का काम देखा था । इन्होंने उस वक्त यह अयोरेंस दी थीं कि उस सड़क को जल्दी पक्का बनवा दिया जाएगा लेकिन वह अभी तक पक्की नहीं बनीं । क्या मंत्री जी फरमायेंगे कि उसे कब तक पक्की बनवा दिया जाएगा ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, यह क्वैचन एक जनरल क्वैचन था । अगर माननीय सदस्य किसी पर्टिकुलर रोड में इंट्रैस्टिड है तो ये उसके लिए नोटिस दे मैं जवाब दे दूंगा ।

मास्टर जोगी राम : स्पीकर साहब, जो सड़क आज मंजूर होती है उस पर भी मिट्टी पड़ती है और जो सड़क 6

महीने बाद मंजूर होती हैं उस पर भी मिट्टी पड़ती हैं लेकिन जिस सड़क पर 6 महीने बाद मिट्टी पड़ती है वह तो पहले बन जाती हैं और पहले वाली रह जाती हैं । क्या मंत्री जी बताएंगे कि उसके लिए पैसा कहां से आ जाता है ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है । अगर माननीय सदस्य इस तरह की कोई बात मेरे नोटिस में लाएंगे तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, एक सवाल तो मुझे आपसे निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष : पूछिए ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इन बैंचिज पर पीछे तक मंत्री लोग बैठे हैं । जब हम खड़े होते हैं तो आप भायद समझते होंगे कि कोई मंत्री ही होगा । हमारी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप जब भी खड़े होते हैं मैं सबसे पहले आपकी टाईम देता हूँ । (विघ्न)

चौधरी बीरेन्दे सिंह : स्पीकर साहब, जिन सड़कों की गवर्नमेंट से ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूबल हो चुकी हैं, महकमें से ऐस्टीमेटस सैंकान हो चुके हैं, उनके बारे में इंजीनियर-इन-चीफ से एस0 ईज0 को एक सर्कुलर गया है और

एस0ईज0 ने उसे आगे ऐक्सीयन्ज को भेजा है उसमें लिखा है कि ऐसी सड़कों पर काम भुरू न किया जाए वर्ल्ड बैंक का पैसा जब अप्रैल या किसी ओर महीने में मिलेगा तब इन पर काम भुरू किया जाएगा। (विघ्न) कल मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि अभी उस पैसे के आने की उम्मीद नहीं है लेकिन ये जल्दी ही उनसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे। मैं जी से पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक से पैसा आने के प्रिटैक्सट पर जो रोडज बंद की हुई है और जिन की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल हो चुकी है उन पर काम कब भुरू करेंगे ?

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, वर्ल्ड बैंक अथोरिटी से हमारी कई मीटिंगें हो चुकी हैं । यह हमारे बस की बात नहीं है कि हम वर्ल्ड बैंक को किसी प्लान को मंजूर कराने के लिए मजबूर कर सकें। हमारी ओर से प्रयत्न जारी है । जब भी वर्ल्ड बैंक से प्लान मंजूर हो जायेगी हम काम भुरू कर देंगे। अब हमारे पास फण्डज नहीं हैं । वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । ज्यों ही फण्डज मिल जायेगें, कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेवान, अब सवालों का समय समाप्त होता है ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Sugar Mill at Palwal

***2759. Shri Mool Chand Mangla :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Sugar Mill at Palwal ; and

(b) if so, the location thereof ?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) इस समय तक कोई स्थान नहीं चुना गया है ।

Registration of Ayurvedic and Unani Practitioners

***2831. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the number of applications received for registration as Ayurvedic and Unani Practitioners during the prescribed period in the State and the number disposed of so far; and

(b) whether any new applications are being received for the purpose, referred to in part (a) above; if so, the total number received during the year ending 28-2-1982 ?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर) :

(क) 24165, सब का निपटान किया जा चुका है ।

(ख) जी हां, दिनांक 1-7-1972 से 28-2-1982 तक 2900 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं ।

Deaths in the custody of Police

***2794. Chaudhri Karam Singh :** Will the Minister for Home be pleased to state the number of deaths, if any, occurred in the State in the custody of police during the last one year ?

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : गत एक वर्ष में पुलिस हिरासत में कथित मृत्यु के दो मुकदमें दर्ज किये गये थे । एक मुकदमा में एफ0आई0आर0 नं 0 147, तिथि 11-6-81 धारा 364/302/201 भा0द0स0 थाना बरवाला दर्ज हुई थी, जो न्यायालय में विचाराधीन है । दूसरा मुकदमा जो नारनौल थाने का है, आत्म हत्या का पाया गया था ।

Patients admitted in Civil Hospital, Sonapat

***2821. Shri Devi Dass :** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the number of patients admitted in Civil Hospital, Sonapat, during the period from January, 1981 to February, 1982; and

(b) the number of patients, if any, out of those referred to in part (a) above, who died together with the names

and addresses of such patients, alongwith the dates on which deaths occurred, separately ?

Health and Tourism Minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar) :

(a) 6614.

(b) 191. The information regarding the names and addresses on such patients alongwith the dates on which the deaths occurred is placed on the Table of the House as Annexure.

Annexure

January 1981 to December 1981

Sr.	Name of patient died	Address	Date of Death
1	2	3	4
1.	Baby Krishna	V.P.O. Dulana Sonapat	2-1-81
2	Omi Devi W/o Kali Ram	V& P.O. Tihar Sonapat	4-1-81
3	Tek Chand S/o Bundi Ram	V & P.O. Baga Sonapat	5-1-81
4	Ash Kumar S/o Ram Nad	Double Manjil Railway line	5-1-81

5	Baby S/o Ram Phal	V & P.O. Raipur Sonepat	9-1-81
6	Sat Narain S/o Dharam Veer	Rajlugari Sonepat	9-1-81
7	Kala Wati S/o Raghubir Singh	H. NO. 929 Ganore	11-1-81
8	Madan Lal S/o Thakur Dass	2/12 Ashok Nagar Sonepat	22-1-81
9	Nayamat Ram S/o Dalja Ram	Jamal Pura Near Sadar	24-1-81
10	Baby S/o Sukhbir Singh	Arya Nagar Sonepat	30-1-81
11	Harphool Singh S/o Ramji Lal	V & P.O. Pritam Pura Sonepat	16-2-81
12	Pappu S/o Jai Pal	V & P.O. Shyamabar Sonepat	9-2-81
13	Khajani S/o Ram Singh	Near Sadar Thana Sonepat	9-2-81
14	Ashoka S/o Jai Pal	V & P.O. Tharu Sonepat	20-2-81
15	Rekha D/o Tulsi Dass	Roop Nagar Sonepat	21-2-81
16	Vasdev S/o Dubuder	Mashed Muhalla	21-2-81

		Sonepat	
17	Ajmat D/o Som Deen	V & P.O. Devru Sonepat	26-2-81
18	Anita D/o Kehar Singh	H. NO. 783, Krishna Pur Ganore	2-3-81
19	Amar Mati D/o Atam Ram	V & P.O. Kherkhoda Near Thana Sonepat	12-3-81
20	Dr. Ram Gopal S/o Krishan chand	V & P.O. Ganore Sonepat	22-3-81
21	Kitabi W/o Surap Singh	Harsana Kalan Sonepat	26-3-81
22	Deepak S/o Ram Niwas	V & P.O. Gohana Sonepat	27-3-81
23	Poonam D/o Ram Kumar	V & P.O. Godwala Sonepat	28-3-81
24	Mukesh S/o Jai Bhagwan	Muhalla Kou Mandi Sonepat	28-3-81
25	Kaka Wati W/o Tola Ram	Jiwan Jagar Sonepat	29-3-81
26	Karan Singh S/o Dario Singh	V & P.O. Nadi Pur Sonepat	31-3-81
27	Un Known /Dario Singh S/o Nanak	-----	11-4-81

	Chand		
28	Dharam Singh	V & P.O. Fajil Pur Sonapat	22-4-81
29	Murti Devi W/o Anoop Singh	Garhi Bhawan Wali Sonapat	23-4-81
30	Radhe Sham S/o Shalu	V & P.O. Garsoli Sonapat	29-4-81
31	Baby D/o Dharam Bir	Near Police Line Sonapat	1-5-81
32	Kisan Chand S/o Chanden Ram	H.NO. 576, Krishan Pura Sonapat	1-5-81
33	Savitari W/o Shriniwas	V & P.O. Mehlana Sonapat	2-5-81
34	Jai Bhagwan S/o Pala Ram	Rathdhana	28-4-81
35	Ram Kumar S/o Zile	V & P.O. Kakroi	2-5-81
36	Takh Singh S/o Jaso Ram	Button Factory Sonapat	2-5-81
37	Kavita D/o Ram Kishan	Jharot	4-5-81
38	Daleep S/o Lahri Singh	Khijan Pur Majra Sonapat	4-5-81

39	T. Majumdar S/o Narain	Muha Kalan Sonapat	5-5-81
40	Bajinder S/o Prithi	V & P.O. Kasoli Sonapat	14-5-81
41	Bhola Singh S/o Vijay Singh	V & P.O. Batganu Sonapat	18-5-81
42	Krishana W/o Girdhan Lal	V & P.O. Jatwara Sonapat	20-5-81
43	Vinod S/o Hukam Chand	V & P.O. Murthal Sonapat	22-5-81
44	Parween S/o Rambir Singh	H.NO. 3/3 Krishan Nagar Sonapat	24-5-81
45	Mukesh S/o Dharam Pal	V & P.O. Near Majra Sonapat	26-5-81
46	kela Devi W/o Ram Krishan	V & P.O. Dandhwa Sonapat	27-5-81
47	Ram Kishan S/o Hari Singh	Do	27-5-81
48	Ram Devi W/o Jesa Ram	Muh Gari Sonapat	28-5-81
49	Dharma W/o Abhey Ram	V & P.O. Jagsi	29-5-81
50	Net Ram S/o Motu	Rajinder Nagar	30-5-81

	Ram	Sonepat	
51	Lalita D/o Rajinder	Rathdhana Sonepat	31-5-81
52	Rambir S/o Manohar Lal	Jat Joboi Sonepat	4-6-81
53	Aruna S/o Dev Anand	H.NO. 5/20 Ashoka Nagar Sonepat	4-6-81
54	Jaswanti Rai S/o Ameer chand	H.NO. 25 Mashed Muhalla Sonepat	4-6-81
55	Surinder Kumar S/o Dharamveer	Shahura Sonepat	5-6-81
56	Dharam Veer S/o Chander Lal	V & P.O. Tajpur Sonepat	6-6-81
57	Diwan Singh S/o Rajuta Singh	Kher Majra Sonepat	8-6-81
58	Bhola Nath S/o Ganesh Dass	Double storey H.NO. 110 Sonepat	9-6-81
59	Rattan S/o Unknown	unknown	10-6-81
60	Khajani w/o Bhartu	Kheri Gujar Sonepat	12-6-81
61	Sant Kumar S/o Kali Deen	Braham Colony Sonepat	12-6-81
62	Tanju S/o Mani Ram	H.NO. 3/148 Prabhu Nagar Sonepat	16-6-81

63	Chand Kaur W/o Chet Ram	Muhala Mashed Sonapat	17-6-81
64	Shish Kaur W/o Bhoop Singh	Kharkhoda Sonapat	20-6-81
65	Menki D/o Subhas	Housing Colony Sonapat	23-6-81
66	Sunil S/o Jaghbir Singh	Railway Stn. Indira Park Bahadurgarh	23-6-81
67	Naresh S/o Hari Chand	Four Marla Sonapat	23-6-81
68	Vajeer S/o Mange Ram	Badhana	26-6-81
69	Rajinder S/o Kalen	V & P.O. Kulana	26-6-81
70	Gian Devi W/o Gurdial	Bara Mandir Kholi Wali Gali Sonapat	27-6-81
71	Seela D/o Shey Ram	Shehjadpur Sonapat	29-6-81
72	Bharpati W/o Daran Singh	Shehjadpur Sonapat	29-6-81
73	Nartum S/o Laxmi Chand	Darwa P.S. Rai	30-6-81
74	Kavita D/o Shiv Chand	D.T. Khana colony Sonapat	4-7-81

75	Shanti W/o Chander	Uleti	8-7-81
76	Seema D/o Seva Ram	Gur Mandi Sonapat	11-7-81
77	Ram Dass S/o Abhey Ram	Kakroi Sonapat	12-7-81
78	Suman D/o Ram Mehtar	Bizlana	17-7-81
79	Rajesh S/o Jille Singh	V & P.O. Gariwala Sonapat	15-7-81
80	Baby Shabo D/o Ram Mehtar	Ganore Sonapat	15-7-81
81	Shinda D/o Jai Bhagwan	Bhatguna	17-5-81
82	Bhushan S/o Daya Nand	Gari Ghaseta Sonapat	21-7-81
83	Un known S/o Unknown	Unknown	24-7-81
84	Baby D/o Huskam Chand	Jatwara	23-7-81
85	Jundei Singh S/o dharama	Majra Pharmaner sonapat	25-7-81
86	Sonu S/o Preetam	Hem Nagar Sonapat	25-7-81
87	Baby D/o Ved Singh	kunda Gadi	27-7-81

88	Raj Pal S/o Ram Kishan	Bhatganu Sonapat	31-7-81
89	Pomby S/o Tilak Ram	Near Sarang Cinema Sonapat	30-7-81
90	Baby D/o Ramesh	Ram Nagar Sonapat	31-7-81
91	Baby Ran Devi D/o Han Chand	Garhi Ghanta Sonapat	1-8-81
92	Chetni W/o Dholu Ram	H.No. 11 Ashok Nagar Sonapat	3-8-81
93	Baby D/o Roshan	Near Railway Phatak Sonapat	4-8-81
94	Papoo S/o Suraj Bhan	V & P.O. Jhari Sonapat	4-8-31
95	Bindu D/o Anut Kumar	H.NO. 74 Model Town Sonapat	5-8-81
96	Veer Bhan S/o Shiv Dayal	V & P.O. Ganer	12-8-81
97.	Baby S/o Birbal	Mohalla Bhaton Kalan	13-8-81
98	Vikas S/o Meh Singh	Pundour Nagar Sonapat	14-8-81
99	Baku Kewri W/o Rattan Singh	Baeyan Pal Sonapat	14-8-81
100	Mehar Dass S/o Kedar Singh	Mishan Road Sonapat	14-8-81

101	Pinki D/o Krishan Chand	V & P.O. Jhari	17-8-81
102	Baldev S/o Kaslu Ram	Ram Nagar Sonapat	17-8-81
103	Janki W/o Chander	V & P.O. Bhidran Sonapat	20-8-81
104	Aruna D/o Om Parkash	Jeewan Nagar Sonapat	21-8-31
105	Sombir S/o Bhaga Singh	V & P.O. Guna Sonapat	21-8-81
106	Puja S/o Gopi Ram	Jamalpur sonapat	23-8-81
107	Bhar Pal w/o Suraj Bhan	H.NO. 707 Ram Nagar Sonapat	25-8-81
108	Om Dutt	Kakpur	29-8-81
109	Baby S/o Sunder	V & P.O. Tihar	28-8-81
110	Nirmal W/o Napha Singh	V & P.O. Mahra	30-8-81
111	Kalla w/o Partap Singh	V & P.O. Kheri	31-8-81
112	Bhole Ram S/o Mukhtiar Singh	Rest House P.W.D.	30-8-81
113	Narang Singh S/o Hoshiar Singh	V & P.O. Hatgon	31-8-81

114	Rattan Lal So Maha Singh	V & P.O. Jatheri	6-8-81
115	Baby D/o Sewa Lal	Industrial Area Sonapat	1-9-81
116	Reeta W/o Maha Singh	Karuaspur Sonapat	2-9-81
117	Kamlesh W/o Gajraj	V & P.O. Tikloa Sonapat	4-9-81
118	Rampat W/o Mahabir Parsad	Old D.C. office Sonapat	6-9-81
119	Bhupinder S/o Raghbir Singh	H.No. 13 Fajli Pur	6-9-81
120	Ajay Kumar S/o Krishan Kumar	Delhi Camp Sonapat	7-9-81
121	Amit S/o Umed Singh	Garhi Ghasita Sonapat	7-9-81
122	Vazeer Singh S/o Dario	V & P.O.Kheri Sonapat	8-9-81
123	Baby S/o Rattan Singh	V & P.O. Garge Sonapat	8-9-81
124	Om Pal S/o Kukhtiar Singh	V & P.O. Khevra, Sonapat	10-9-81
125	Baby Phoolwati D/o Ram Chander	V & P.O. Shamli, Sonapat	10-9-81

126	Sunita D/o Ram Kumar		12-9-81
127	Ganga Devi W/o Raghubir	Garhi Ghasitan, Sonapat	15-9-81
128	Mohan Tondon W/o Manjeev Singh	H.NO. 236 Model Town Sonapat	15-9-81
129	Vajinwer S/o Vishnu	V.P.O Badhna, Sonapat	15-9-81
130	Pushpa Rani W/o Ved Parkash	Mashed Mohalla, 302, Sonapat	17-9-81
131	Tej Singh S/o Prabhu Ram	V.P.O. Mahipur, Sonapat	18-9-81
132	Baby S/o Ramphal	Ganore	21-9-81
133	Risal Singh S/o Mool Chand	Abir Majra, Sonapat	21-9-81
134	Pappu S/o Chand Ram	West Ram Nagar, Sonapat	23-9-81
135	Geeta D/o Om Parkash	Dev Nagar Sonapat	26-9-81
136	Jogi Ram S/o Moji Ram	Police Post Murthal	27-9-81
137	Sawarn Kaur D/o Jai Singh	V & P.O. Bhagwan Sonapat	29-9-81

138	Sharmila D/o Mozi Ram	V & P.O. Maherudabad, Sonapat	29-9-81
139	Ram Chander S/o Dharam Pal	V & P.O. Hasanpur, Sonapat	30-9-81
140	Poonam D/o Karan Singh	Old D.C. Office, Sonapat	2-10-81
141	P. Malik S/o B.N. Malik	Hindustan Reading Wiring Bahalgarh	9-10-81
142	Ram Kawal S/o Ram Ratti	Omi Textile Mill, Sonapat	10-10-81
143	Renu D/o Ram Lal	House NO. 82, MOhalla Mashed Sonapat	12-10-81
144	Birmati D/o Laxmi	V & P.O. Jhari Sonapat	14-10-81
145	Hoshiar Singh S/o Khem Ram	Bahalgarh, Sonapat	17-10-81
146	Ranjeet Singh s/o Gugan	V.P.O. Bharvansni Sonapat	17-10-81
147	Santosh W/o Puran Chand	Sarang Road, Sonapat	20-10-81
148	Kesho Ram S/o Badlu Ram	Pharmana, Sonapat	25-10-81
149	Parwati W/o Gupteshwar	Kulupur Chungi, Dharam Nagar Sonapat	25-10-81

150	Baby NInda D/o Ram Phel	Ashoka Nagar, Sonapat	26-10-81
151	Kalap Nath S/o Ram Karan	Roop Nagar, Sonapat	30-10-81
152	Shish Ram S/o Abhey Ram	Gur Mandi Sonapat	1-11-81
153	Munna S/o Prem Singh	Niwas Pur, Sonapat	2-11-81
154	Harbans S/o Teja Ram	MOhalla kalan Sonapat	3-11-81
155	Bihari Lal S/o Abu Ram	Mohall Kalan Sonapat	4-11-81
156	JOgi Ram S/o Punna	Shekhupura	5-11-81
157	Krishna W/o Om Parkash	Bhutana	6-11-81
158	Baby Phoolwati D/o Balwan Singh	Hasanpur	8-11-81
159	Kali Ram S/o Tale Ram	Rajlugarhi	10-11-81
160	Risalo W/o Naphe Singh	Junva	10-11-81
161	Shri. Gopal S/o	Bara Bajar, Sonapat	9-11-81

	Harbans		
162	Chandgi Ram S/o Nathu Ram	Saleem Sar Majra	17-11-81
163	Shri. Ram S/o Harphool Singh	Mahlana	23-11-81
164	Chhaju Ram S/o Nathu	Shiv Nagar, Sonapat	23-11-81
165	Unknown	Unknown	27-11-81
166	Sandeep S/o Hawa Singh	Bhatganv, Sonapat	28-11-81
167	Tulsi Bai S/o Parma Nand	Hem Nagar, Sonapat	29-11-81
168	Randhir S/o Kishan	Bal Ranghdala, Sonapat	30-11-81
169	Darshan S/o Jawahar singh	Ashok Nagar, Sonapat	1-12-81
170	Kartar S/o Dhoop Singh	Bilaspur	3-12-81
171	Pale Ram S/o Pyare Lal	Model Town, Sonapat	4-12-81
172	Lajwanti w/o Hans Raj	Housing Colony, Sonapat	5-12-81
173	Baby S/o Bhag Raj	Raja Colony, Sonapat	5-12-81

174	Baby S/o Bhag Raj	Raja Colony Sonapat	5-12-81
175	Sham Devi W/o Dhanu Ram	Ashok Nagar, Sonapat	7-12-81
176	Kuldip S/o Pyare Ram	Ram Nagar, Sonapat	19-12-81
177	Roop Chand S/o Nathu Ram	V & P.O. Jhahi	25-12-81
178	Nihali W/o Chet Ram	kakroi	28-12-81
179	Sushila W/o Ram Dass	Sikka Colony, Sonapat	28-12-81
180	Ashok S/o Tuli	Devru	31-12-81
January 1982 & Februrary 1982			
1	Nana S/o Amar Singh	Rarsoli	3-1-82
2	Tej Bir S/o Karam Singh	Chitawalia, Sonapat	16-1-82
3	Goverdhan S/o Daya	Rattangarh	19-1-82
4	Baljeet Singh S/o Hawa Singh	New Mahavir Colony, Sonapat	19-1-82
5	Hargobind S/o B.D. Diwan	Model Town, Sonapat	1-2-82
6	Hem Raj S/o Deval Ram	Model Town, Sonapat	29-1-82

7	Laxman S/o Ratti Ram	Mandi	24-1-82
8	Ashok Kumar S/o Ram Lal	Panipat	3-2-82
9	Soma Devi S/o Ganpat	Bhagan, Sonapat	8-2-82
10	Om Parkash S/o Rattan Singh	Arya Nagar, Sonapat	10-2-82
11	Parmeshwari W/o K.R. Sharma	Sudama Nagar, Sonapat	27-2-82

Compensation for the construction of Canals

***2480. Shri. Surrender Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any compensation is yet to be paid in respect of the land acquired for the construction of Jui Canal, Siwani Canal, Loharu Canal and their minors and sub-minors if so, total amount thereof; and

(b) the names of the persons who are still to be paid the compensation, as referred to above ?

Irrigation & Power Minister (Sardar Tara Singh) :

(a) Yes. Rs. 14.65Lacs.

The names of the persons who are still to be paid compensation shall be available as and when the awards are announced.

30 Bed Hospital at Dabwali

***2855. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the government to construct 30 Bed Hospital at Dabwali; and

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर) :

(क) जी नहीं। किन्तु यहां पर 50 बिस्तर के अस्पताल का भवन बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) निर्माण कार्य धन उपलब्ध होने पर आरम्भ किया जाएगा। अवधि बारे इस समय बताना संभव नहीं है।

Recruitment make in Land Development Bank etc.

***2815. Ch. Gaya Lal:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state:-

(a) Whether the policy of making reservation for the persons belonging to Scheduled Castes is being complied with while making recruitment/promotions on various posts in the Land Development Bank and other Cooperative Institutions in the State; and

(b) The total number of officials/officers of different categories, in the Haryana State Land Development Bank together with the number amongst them belonging to the Scheduled Castes at present?

Cooperation and Planning Minister (Thankur Bir Singh):

(a) Govt. instructions regarding reservations have been made applicable in cooperative institutions in the State. However, there is some shortfall which these institutions have been advised to make up.

(b) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Position of Staff as on 4-3-82 of Haryana State Co-operative land Development Bank Ltd.

Sr. No.	Name of the Post	Total strength	S.C.
1.	Managing Director	1 (on deputation)	--
2.	Additional Secretary	1	--
3.	Secretary	1	--
4.	Additional Secretary	1	--
5.	Faculty Incharge	1	--

6.	Deputy Secretary	1	--
7.	Agricultural Economist	1 (on deputation)	--
8.	Assistant Secretary	2+1(on deputation)	--
9.	Chief Inspecting Officer	1 (on deputation)	--
10.	Additional C.I.O.	1	--
11.	Project Officer (Dairy Development)	1 (on deputation)	--
12.	Horticulture Development Officer	1 (on deputation)	
13.	Statistical Officer	1	--
14.	Inspecting Officer	6	--
15.	Law Officer	4	--
16.	Managers/Accountants	50	1
17.	Junior Acctt./Assistant	61	11
18.	Senior Scale Stenographer	3	--

19.	Junior Scale Stenographer	4	--
20.	Field Officers	25	2
21.	Land Valuation Officer	291	6
22.	Clerks	339	21
23.	Dairy Development Asstt.	6 (on deputation)	-
24.	Drivers	29	2
25.	Daftri	7	1
26.	Peons/Chowkidar/Sweeper	45	9
27.	Technical Asstt.	3	9
Total		887	53

**Installation and damaging of Electric Poles in
Village Sankhera under Sadhaura Sub-division**

***2828. Ch. Bhag Mal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) Whether any poles installed in the first week of Feb, 1982 in Sankhera village by the H.S.E.B. staff of Bilaspur (under Sadhaura sub-division) to give connection to the tubewell of harjian of that village;

(b) Whether any poles, out of those referred to in part (a) above, were unauthorisedly uprooted and damaged; and

(c) If the reply to part (b) above be in the affirmative, whether any F.I.R. has been lodged at Bilaspur police station against the persons, referred to in part (b) above; if so, the details thereof ?

Irrigation & Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) Yes, 11 NOs. poles were erected for releasing the tubewell connection to one Shri Lachna Ram, a harijan applicant of village Sankhera.

(b) 4 Nos. poles were found unauthorisedly uprooted and damaged.

(c) Yes, An F.I.R. has been lodged with Bilaspur Police Station to the effect that some one had up-rooted and broken 4 poles resulting in a loss of about Rs. 1520/- to the Board.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Educated unemployed youth in the State

659. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Exce and Taxation be pleased to state:-

(a) The districtwise total number of educated unemployed youth registered with the Employment Exchanges in the State at present; and

(b) The districtwise number of unemployed youth out of those referred to in part (a) above, provided employment during the period from 1-8-81 to date, separately?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी) :

(क) दिनांक 28-2-1982 को रोजगार कार्यालय में दर्ज शिक्षित प्रार्थियों की जिलावार संख्या निम्न हैं:-

क्रम संख्या	जिला	प्रार्थियों की संख्या
1.	अम्बाला	29785
2.	भिवानी	13214
3.	फरीदाबाद	10978
4.	गुड़गांव	12502
5.	हिसार	16439
6.	जीन्द	11331
7.	करनाल	29575
8.	कुरुक्षेत्र	13064
9.	महेन्द्रगढ़	13088
10.	रोहतक	23345

11.	सिरसा	8149
12.	सोनीपत	11322
टोटल		192792

नोट:- "शिक्षित प्रार्थी" उन्हें माना जाता है जो कम से कम दसवीं पास हों ।

(ख) दिनांक 1-8-81 से 28-2-82 तक नौकरी पर लगे शिक्षित प्रार्थियों की जिलावार संख्या निम्न हैं:-

क्रम संख्या	जिला	नौकरी पर लगे प्रार्थियों की संख्या
1.	अम्बाला	1138
2.	भिवानी	773
3.	फरीदाबाद	642
4.	गुड़गांव	340
5.	हिसार	1030
6.	जीन्द	635
7.	करनाल	754

8.	कुरुक्षेत्र	688
9.	महेन्द्रगढ़	881
10.	रोहतक	1057
11.	सिरसा	438
12.	सोनीपत	648
टोटल		9564

Stadia in the State

660. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) The names of the sport stadia existing in the State at present together with the latest position of such stadia which are under construction and the total expenditure incurred on the completed and under construction stadia todate, separately; and

(b) The date/dates by which the stadia under construction are likely to be completed separately?

Transport Minister (Shri Jagan Nath):

(a)(i)	Existing Sports Stadia in the State	Expenditure incurred thereon
1.	Motilal Nehru Stadium, Karnal	Rs. 8,47,917.58 P

2.	Nehru Stadium, Jind	Rs. 5,48,865.46 P
3.	Nehru Stadium Hissar	Rs. 9,28,600.00 P
4.	Nehru Stadium, Gurgaon	The possession of this stadium was transferred to the Distt. Stadium Committee, Gurgaon by the Zila Parishad in 1970.

(ii)	Stadia under Construction	Latest position of the Stadia	Expenditure
1.	Bhiwani	completed upto first phase	Rs. 16,60,552.29 P
2.	Sonepat	A part levelling of the site has been made.	Rs. 56,939.45 P
3.	Sirsa	Boundary wall has been	Rs. 7,93,800.00P

		completed. Steps, earth work, retaining wall in progress.	
4.	Panipat(Karnal)	The boundary wall, earth filling and gates provided on the site.	Rs. 1,55,299.18P
5.	Rewari (Narnaul)	The front wall upto plinth level has been completed.	Rs. 50,000.00P
6.	Issarwal (Bhiwani)	Playground levelled and boundary wall completed.	Rs. 20,000.00P
7.	Chautala (Sirsa)	Boundary wall and platform constructed, earth work	Rs. 3,03186.64P

		done.	
8.	Ambala	A tubewell has been sunk for providing water to the swimming pool alongwith hydrants in the playground. Basketball ground completed.	Rs. 2,33,302.00P
9.	Yamuna Nagar (Ambala)	Work of seating arrangement and levelling of ground has been completed.	Rs. 6,05,000.00P
10.	Faridabad	Work for the development of play grounds has started.	Rs. 32,000.00P

(b)	Name of Stadia under construction	Dates on which these are likely to be completed
1.	Bhiwani	First phase already completed. II phase is expected to be completed in the next three years.
2.	Sonepat	Since this work is held up because of encroachment on a part of the land hence it is not possible to give any date by which the work would be completed.
3.	Sirsa	This work is expected to be completed in the next two years.
4.	Panipat (Karnal)	This work is expected to be completed in the next two years.
5.	Rewari (Narnaul)	This work is expected to be completed in the next two years.
6.	Issarwal (Bhiwani)	This work is expected to be completed in the next two

		years.
7.	Chautala (Sirsa)	This work is expected to be completed in the next three years.
8.	Ambala	This work is expected to be completed in the next three years.
9.	Yamuna Nagar (Ambala)	This work is expected to be completed in the next three years.
10.	Faridabad	This work is expected to be completed in the next three years.

Projects under the World Bank Schemes

661. Ch. Ram Lal Wadjwa: Will the Minister for Cooperation be pleased to state:--

(a) The names of schemes/projects sanctioned under World Bank Schemes in the State during the last three years (to-date) togetherwith the amount sanctioned for each project, separately; and

(b) The scheme-wise/project-wise amount received from World Bank and the amount spent thereon, as referred to in part (a) above, to-date, separately?

Interim Reply

Subject:- Unstarred Vidhan Sabha Question No. 661 by Ch. Ram Lal Wadhwa M.L.A. regarding projects under the World Bank Schemes.

The Unstarred Assembly Question No. 661 appearing in the list of Unstarred Questions for the 31st March, 1982 in the name of Minister for Cooperation is not ready.

2. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

Planning and Cooperation

Minister, Haryana.

To

The Secretary ,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

U.O. NO. 40/15/81-plg, dated Chandigarh, the 30th March, 1982.

Tour of Chief Minister

662. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) The monthwise number of days the State Chief Minister remained on tour outside Chandigarh, togetherwith the number of days of his stay at Delhi/New Delhi, during the period from 1-4-81 to date, separately; and

(b) The amount of T.A. drawn by the Chief Minister for the tours, as referred to in part(a) above, separately?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): एक विवरणी (अनुबन्ध "ए") जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन के पटल पर रखी जाती हैं ।

‘अनुबन्ध ए’

भाग	(क)	4 / 81	5 / 81	6 / 81	7 / 81	8 / 81	9 / 81	10 / 81	11 / 81	12 / 81	1 / 82	2 / 82
(i)	राज्य के मुख्य मंत्री के 1-4-81 से आज तक (28-2-82) की अवधि में चण्डीगढ़ से बाहर दौरे पर रहने वाले दिनों की मास वार	22	18	26	16	23	18	18	21	17		अभी तक 1 / 82 तथा 2 / 82 का यात्रा भता प्राप्त नहीं किया।

	संख्या											
(ii)	राज्य के मुख्य मंत्री के 1-4-81 से आज तक (28-2-82) की अवधि में दिल्ली / नई दिल्ली में ठहरने वाले दिनों की मासवार संख्या	19	5	8	13	7	11	8	15	14		-यथोपरि-

भाग (ख)

ऊपर के भाग "क" में यथा निर्दिष्ट दौरों के लिए मुख्य मंत्री द्वारा यात्रा भता के रूप में प्राप्त की गई राि ।	1702 7 / 81 में भुगतान हुआ	1765. 75 8 / 81 मे भुगतान हुआं	--	918 9 / 81 में भुगतान हुआ	*36862	1899. 75 12 / 81 में भुगतान हुआ ।	1535 1 / 82 में भुगतान हुआ ।	1287. 75 1 / 82 में भुगतान हुआ ।	1275 2 / 82 में भुगतान हुआ ।		-यथोपरि-
---	--	---	----	---------------------------------------	--------	--	--	---	--	--	----------

*36862 रूपये 2-8-81 से 16-8-81 तक विदे । के दौरे से संबंधित हैं ।

Non-Directory Villages in the State

705. Shri. Mool Chand Jain: Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) Whether there are may non-directory villages having separate abadis, which are not being considered as revenue estates independently, in the State; if so, tehsil-wise names therefo; and

(b) Whether the Government has received any representation that non-directory villages, as referred to in part (a) above, existing in Panipat tehsil, be converted into directory villages; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House togetherwith the action, if any, taken thereon ?

***Interim Reply**

D.O.No. 2617-R-IV-82/11460

Sher Singh,

REVENUE MINISTER

Dated the 30th March, 1982.

Subject:- Unstarred Assembly Question No. 705 regarding non-directory villages in the State.

My dear Rao Sahibji,

The Unstarred Assembly Question No. 405, asked by Shri Mool Chand Jain, M.L.A. has been fixed for reply on 31-3-1982. Notice for the question was received in Revenue Department on 25-3-1982 at 4.50 P.M. The

reply to the question is not ready as the required information is still awaited from the Deputy Commissioners, Karnal, Faridabad, Rohtak and Sirsa.

2. I shall be grateful if you kindly extend the time for answering the question under rule 46(ii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. The question may be included in the list of questions for any date after ten days.

with regards,

Yours

sincerely,

Sd/-

(Sher Singh)

Shri Ram Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Inclusion of village Saori In Tehsil Assandh

706. Shri. Mool Chand Jain: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the Government has received any representation against the inclusion of village Saori in Assandh Tehsil; if so, a copy thereof be laid on the

Table of the House, togetherwith the action, if any, taken thereon?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): हां प्रतिवेदन की एक प्रति अनैक चर "ए" पर हैं। मामला निरीक्षणधीन हैं।

ANNEXURE 'A'

सेवा में

श्री मान राजस्व वितायुक्त महोदय, हरियाणा
चण्डीगढ़।

विशय:— दरखास्त बाबत निकाले जाने ग्राम सयोडी
असन्ध तहसील व भामिल किये जाने
करनाल तहसील में।

श्री मान जी,

सेवा में निवेदन हैं:—

1. यह कि सयोडी गांव नई तहसील असन्ध में भामिल कर लिया गया है। जब कि उस के पड़ोसी गांव गोन्दर को करनाल तहसील में रखा है। ग्राम सयोडी बेचरागन मोजा है और इस की कसर भूमि के मालिकान गोन्दर के निवासी हैं और गोन्दर की आबादी में ही उनके मकानात रिहाई हैं।

2. यह कि यातायात के साधन भी असन्ध जाने के लिए कोई नहीं हैं। जब कि नीसिंग सब तहसील में जाने के लिये पक्की सड़क हैं नीसिंग सयोडी से 2 मील पर स्थित हैं और जब कि असन्ध सयोडी से 14-15 मील पर स्थित हैं ।

इसलिये प्रार्थना हैं कि ग्राम सयोडी को असन्ध तहसील से निकाल कर करनाल तहसील और सब तहसील नीसिंग में मिलाया जावे आपकी अति कृपा होगी।

निवेदक

इत्यादि

गेन्दाराम पुत्र वजीर गांव सयोडी

करनाल तिथि 16-11-81 तहसील, जिला करनाल

हस्ता: गेन्दा राम

हस्ता: बलकार सिंह पुत्र श्री

आत्मा सिंह निवासी गोन्दर

नि गान अंगूठा

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इरीगे गान डिपार्टमेंट के एक अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वह अधिकारी अपने नीचे काम कर रहे अधिकारियों और वि शेषकर

महिला कर्मचारियों को परे पान करता रहा है। उसकी विजिलैन्स से इन्क्वायरी हुई। उस पर चार्ज साबित हुए। जब उसे चार्ज पीट किया जा रहा था तो एक मिनिस्टर बीच में पड़ गया है कि चार्ज पीट सर्व करने से पहले मुझे दिखा देना। वह अभी तक चार्ज पीट नहीं हुआ। मैं इस ओ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब इन्क्वायरी में चार्ज साबित हो चुका हो.....
.. (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जहां तक इंडीविजुयल के कंडक्ट का सवाल है जो आदमी हाउस में मौजूद नहीं है और अपने आप को डिफैक्ट नहीं कर सकता उसके बारे में हाउस में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री जय नारायण वर्मा : यह गवर्नमैट की वर्किंग का सवाल है। अगर कोई इंडीविजुयल अफसर कसूरवार है तो उसे चार्ज पीट कर दें।

श्री अध्यक्ष: आप कोई सबस्टांटिव मो पान दें। अगर वह एडमिट हो सकती होगी तो मैं कर दूंगा।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल-अटैन् पान मो पान दी थी। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने जो काल-अटैन् पान मो पान दी है अगर वह एडमिट हो सकेगी तो जरूर करूंगा। (गोर एवं व्यवधान)

डा० मंगल सैन : स्पीकर साहब, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज कुरुक्षेत्र में पिछले साल नवम्बर से हरिजन विद्यार्थियों पर हमले हो रहे हैं। वहां से पुलिस कप्तान के लड़के ने गोली चला दी। बीस तारीख को एक नौजवान लड़की पर कातलाना हमला हुआ।

श्री अध्यक्ष: आप इस बारे में सबस्टांटिव मो इन भेजिए।

डा० मंगल सैन : स्पीकर साहब बड़ा अफसोस हैं। मेरा आदमी सुबह 8 बजकर 20 मिनट पर मो इन लेकर आया लेकिन उस पर 8 बजकर 30 मिनट का टाईम डाल दिया गया। यह बड़ा सीरियस मैटर हैं। इस बारे में मुझे एतराज हैं। जब मैं नोटिस सोच-समझ कर भेजता हूं और इन एडवांस कापी भेजता हूं फिर भी कार्यवाही नहीं होती। हरिजन लड़कों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा हैं। एस० पी० श्री नकई के लड़के का उसमें हाथ हैं।
(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसे मैं एग्जामिन करूंगा।

चौधरी अजीत सिंह : स्पीकर साहब, हजारों गरीब हरिजनों को सरप्लस भूमि नहीं दी जा रही है। मेरे पास ऐसे उदाहरण है। कि लोगों ने चालान भर दिए हैं, जमीन के पैसे दे दिये हैं लेकिन उनकी बेदखली कर रहे हैं एक तरफ यह सरकार

कहती कि हम हरिजनों को सरप्लस लैन्ड दे रहे हैं और दूसरी और उनको बेदखल कर रहे हैं । (तोर एवं व्यवधान)

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, यह सरकार हरिजन विरोधी है । इसलिये मैं सदन से वाक आउट करता हूँ ।

(इस समय श्री भागी राम सदन से वाक-आउट कर गये ।)

चौधरी जय नारायण: स्पीकर साहब, यह सरकार हरिजनों के साथ अन्याय कर रही है । हरिजनों की कोई सुनवाई नहीं हो रही । इसलिये मैं भी सदन से वाक-आउट करता हूँ ।

(इस समय चौधरी जयनारायण तथा विरोधी पक्ष के अन्य हरिजन सदस्य सदन से वाक-आउट कर गये ।)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वाक-आउट की भी बड़ी भारी इनसल्ट कर रखी है । ये वाक-आउट करने का स्तर भी बहुत नीचे ले आये हैं ।

श्री मूल चन्द जैन: जितनी नीचे यह सरकार चली गई उतना ही नीचे वाक-आउट चला गया ।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

चौधरी भागमल: स्पीकर साहब, किसी हरिजन को एक ट्यूबवैल का कनैक्टान मिलना था लेकिन उस गांव के जमींदारों

ने उसे कनैव तन नहीं लेने दिया। तीन चार खम्भों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। यह बिलासपुर हल्के का केस है। (गोर)

श्री अध्यक्ष : अगर किसी इंडीविजुयल का केस है, उसे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई मर्डर हो गया, रेप हो गया तो बात करने का स्कोप बन सकता है लेकिन किसी ने खम्भे उखाड़ कर फेंक दिये, इस तरह के केस हाउस में नहीं आने चाहिए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, जिसने खम्भे उखाड़े थे हमने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार किया है।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मैं मैम्बरज के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। कामरेड भांकर लाल, कैप्टन मांगे राम, राव राम नारायण आदि को एक ही लाईन में बैठाया है। (हंसी) दूसरी बात यह है कि विधान सभा में दो मैम्बर हैन्डीकैप्ड हैं। एक तो लाठी के सहारे से चल सकते हैं लेकिन दूसरे पूरी तरह हैन्डीकैप्ड हैं। मेरी आपसे गुजारि है कि चौधरी गंगा राम को हाउस से निकाले हुए काफी दिन हो गए हैं इसलिये मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि उन्हें वापिस बुला लें। काफी दिन हो गए हैं इसलिये मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि उन्हें वापिस बुला लें।

श्री अध्यक्ष: वैसे वे डिस्-एबल्ड हैं। उन्होंने मेरे को दरखास्त दे दी है उनके लिए हमने बम्बई से कार का अरैन्जमेंट

कराया हैं। बम्बई में उनके ठहरने का भी पूरा इन्तजाम कर दिया गया है। वे डेढ़ लाख की कार ले कर आयेगें।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मैंने दो काल अटैन्शन आपको भेजी थी। ऐ भांगर-केन की कीमत के बारे में थी और दूसरी चने सरसों और सब्जियों का जो नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे में बारे में थी।

श्री अध्यक्ष: भांगर-केन की कीमत के बारे में आपने जो काल-अटैन्शन माँगा था, वह एडमिट हो गई है।

श्री मूल चन्द जैन: चने और सरसों की फसल को जहाँ नुकसान हुआ है या सीवेज से जहाँ नुकसान हुआ है क्या उसका मुआवजा सरकार देगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री ये अनाउन्स कर चुके हैं कि स्पैल गिरदावरी की जा रही है। जिस प्रकार से गेहूँ की गिरदावरी की जा रही है, उसी प्रकार से चने और सरसों की गिरदावरी में मैंने अटैन्शन किया है। 3

श्री मूल चन्द जैन: उन्होंने सिर्फ ओले से जो नुकसान हुआ है उसके बारे में अनाउन्स किया है लेकिन जो भीत लहर या ज्यादा वर्षा से नुकसान हुआ है वह भी मैंने अपनी माँगा में अटैन्शन किया है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैंने कल ही स्टेट के डिप्टी कमीशनर की मीटिंग बुलायी थी। हमने स्पष्ट की थी उनके जिम्मे यह काम लगाया है कि ओले, भीत लहर या सीपेज से सरसों, तोरिया, तारामीरा, चने या गेहूँ यानी चाहे किसी भी फसल को नुकसान हुआ है, उसकी गिरदावरी करे। जिसका जितना और जिस रेटों से मुआवजा बनता है, उसको मुआवजा दिया जाये। हमने आज ही इसके लिये 5 करोड़ रुपया रिलीज करने का फैसला किया है। उसके बाद अगर मुआवजा देने के लिये और रुपये की जरूरत पड़ी तो और भी देगे।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा:

चौधरी भजनलाल: स्पीकर साहब, ऐसे लोग मैम्बर बनकर आ गये हैं, यह इस हाउस की बदकिस्मती हैं। यह तो जनता बतायेगी कि कौन जाता है और कौन नहीं जाता है। अगर इनकी जमानत भी बच जाये तो मुझे कहना (व्यवधान)

Mr. Speaker: Whatever has been said by Chaudhri Hari Chand Huda may be expunged.

चौधरी हरिचन्द हुड्डा:

.....

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

श्री उप मंत्री (चौधरी लाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक दरखास्त करना चाहता हूँ। इज्जत से बड़ी

इस दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं हैं। इनको सभी की इज्जत का ख्याल करना चाहिए।

स्वामी अग्निवे 1: अध्यक्ष महोदय, जिन दिनों आप शिक्षा मंत्री थे, उस समय आपने ऐ बहुत अच्छी तजबीज दी थी कि छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन पर किताबों का बोझ काफी बढ़ता जा रहा है, इसलिये कत किया जाय। आपकी तजबीज यह थी कि इन किताबों को कम किया जाये और बच्चों को खेलकूद या काम के जरिये ज्यादा पढ़ाई कराई जाय। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: उस वक्त आप एजुके ान बोर्ड के चयरमैन थे। मैंने यह काम आपके जिम्मे लगाया था। (व्यवधान व भाोर)

स्वामी अग्निवे 1: मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। उस समय जनता पार्टी की शिक्षा के बारे में जो नीति थी, उसके तहत हमने शिक्षा बोर्ड के अन्दर भी इस चीज को स्वीकार किया था और कुछ सिलेबस को कम करना भी स्वीकार किया था। आप के बाद जब श्री हीरा चन्द आर्य जी शिक्षा मंत्री बने उन्होंने उसको फालो किया और मैंने भी उसको फालो किया। लेकिन जब से चौधरी देस राज जी शिक्षा मंत्री बन हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं इस बारे में किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाता हूँ। मैं तो शिक्षा मंत्री जी से केवल यह जानना चाहूंगा कि क्या उन बच्चों के किताबों के बोझ को कम कर रहे हैं या नहीं? मैं

यह कहता हूँ कि राजनीतिक विरोध की बात को छोड़ दें। यह स्पीकर साहब के शिक्षा मन्त्रित्व काल या किसी ओर के समय का सवाल नहीं है। मैं तो उनसे सीधा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या बच्चों के किताबों के बोझ को कम करने के बारे में ध्यान दिया है या नहीं ताकि माता-पिता का खर्च भी कम हो और बच्चों को भी आसानी हो सके। (व्यवधान व भाोर)

शिक्षा मंत्री (चौधरी देसराज): स्वामी जी ने तो केवल फालो ही किया था लेकिन हमने एक कमेटी बनाकर 25 प्रतिशत कोर्स पहली जमात से लेकर चौथी तक का कम कर दिया है। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तो सब कुछ अच्छे माहौल में हो रहा है। एक दो दिन की बात और बाकी रहती है। हर आदमी अच्छे माहौल की बात कर रहा है। हमारे एक मैम्बर ने आपको लिखकर शिक्षा मन्त्रित्व की है कि मुझे एक कमेटी से इन्साफ की उम्मीद नहीं है। 35 साल की हिस्टरी में ऐसी शिक्षा मन्त्रित्व आज तक किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने हमारी कमेटी इल्जाम लगाया है कि एक ही कौम के ज्यादा मैम्बर उसमें हैं इसलिये उनको इन्साफ मिलने की कम उम्मीद है। उस आनरेबल मैम्बर की दरख्सात रिकार्ड में है। मेरा कहना यह कि उस मैम्बर को हाउस से निकाल दिया जाये क्योंकि कमेटी की बेईज्जती की है और उसको इस हाउस में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: मैंने वह डाकुमैट कमेटी को रैफर कर दिया है। उस कमेटी के मैम्बरज उस बारे में जो भी निर्णय लेना चाहें, ले लें। (व्यवधान व भाोर)

मैम्बर साहेबान, पब्लिक अन्डरटेकिंगज कमेटी का इन्वैकान होना था जिसमें 10 कान्टैस्टैट्स थे। जिनमें से चौधरी सुरेन्द्र सिंह, एम0 एल0 ए0 विदद्वा करने की इजाजत दे दी जाये।

आवाजें: ठीक हैं जी।

श्री अध्यक्ष: चौधरी सुरेन्द्र सिंह, एम0 एल0 ए0 के बिदद्वा करने के बाद 9 कान्टैस्टैट्स रह जाते हैं। उसके बाद इन्वैकान की जरूरत नहीं है। यह 9 के 9 इन्वैक्टिड समझे जायेंगे। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी संत कवर: स्पीकर साहब, चौधरी सुरेन्द्र से इसीलिये बिदद्वा करवाया गया है क्योंकि पिछले दिनों 3 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें कमेटी ने एक सदस्य जो कार्पोरेकान के चेयरमैन हैं, के खिलाफ रिपोर्ट एडाप्ट की थी। (व्यवधान व भाोर) क्या इसलिये उनसे बिदद्वा करवा गया है?

ध्यानाकर्षण सूचना—

जिला महेन्द्रगढ़ तथा जिला रोहतक की कोसली तहसील के बहुत ज्यादा पिछेड़पन तथा गरीबी की हालत होने सम्बधी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज मुझे राव राम नारायण एम0 एल0 ए0 की ओ से डिसिट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ और रोहतक की कोसली तहसील के पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने चाहिये। इसके बारे में एक काल अटैन्शन मोशन प्राप्त हुआ है। मैं इसको मन्जूर करता हूँ। राव राम नारायण, एम0 एल0 ए0 अपना नोटिस पढ़ दें। मंत्री महोदय अपनी स्टेटमेंट दे दें। (व्यवधान व भाोर)

Rao Ram Narin: Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of public importance that the present Mohindergarh District, Kosli. Tehsil of District Rohtak are extremely backward and poor. There is historical background to all this. People of this area took active part in first war of Independence of 1857 against the Britishers. It was mostly the part of Jhajjar State of that time. Nawab of Jhajjar was hanged in Chandhi Chowk for his conspicuous part played by him in war of Independence of 1857. The Britishers partitioned this area in different Blocks and gave each Block to princely States of Patiala, Nabha and JInd. These areas were far away from their Headquarters and so on development was made. Even after Independence in 1947, the area remained neglected.

In order to remove its backwardness and poverty the Government may take the following steps:-

(i) South Haryana Development Board may be constituted as has been done in the case of Mewat area.

(ii) Engineering college and Law College may be opened at Rewari.

(iii) Polytechnical college at Ateli should be opened.

(iv) Regional centre for Post Graduate Studies and Research at Rewari may be started at once. U.G.C. aid may be had for this.

(v) Sainik school may be opened in this area—preferably at Kosli.

(vi) Army recruitment office may be started at Rewari as it was before.

(vii) Agriculture college under H.A.U. Hissar may be opened at Narnual.

(viii) Big factories may be installed in the area and 80% labour should be of this area.

(ix) Some important offices of the State and Centre may be opened in this area.

This is a matter of great public importance. Government is requested to make a statement as to what steps the Government propose to take in order to remove the poverty and backwardness of this area.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इसका जवाब हम दो तारीख को देगे ।

वक्तव्य—

(i) खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा राज्य में सीमेंट, चीनी, मिट्टी का तेल व कुर्किंग गैस का वितरण सामान्य न होने सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष: फूड एण्ड सप्लाइज मिनिस्टर ने सर्वश्री अजीत सिंह, फतेह चन्द विज, जय नारायण खुंडिया और देवी दास के काल अटैन्शन मोशन 23 और 46 का आज जवाब देना था। वे अब अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, ऐ प्रिविलेज मोशन मैंने भी दिया था

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी यह जीरो आवर नहीं है। जीरो आवर में मैंने आपको टाईम दिया था अगर हर समय ही यह बात करने लगे तो इससे हाउस की कार्यावाही रुक जाती है।

स्वामी अग्निवेश: उसका जवाब तो आना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक भाई नोटिस क्वैशन भी दिया हुआ है... ..।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी आप मेरे चैम्बर में आ जाएं। वहां मैं बता दूंगा। अब मंत्री महोदय अपना स्टेटमेंट पढ़ें।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री लखमन सिंह): मैं यह बात भुरु में ही स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य में सीमेंट, चीनी, मिट्टी के तेल तथा जलाने वाली गैस की उपलब्धि इतनी नहीं

है कि यह उपभोक्ताओं की सारी मांग को पूरा करने के लिए प्रयाप्त हो। परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि इन वस्तुओं की राज्य द्वारा अनुचित बांट की जाती है या इस कथित अनुचित बांट के कारण आम जनता में असंतोश है। सीमेंट की वितरण प्रणाली में अभी अभी भारत सरकार ने परिवर्तन किया है और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इसका आंशिक डीकण्ट्रोल कर दिया गया है। चीनी की बांट दोहरी कीमत की नीति के अधीन की जा रही है और जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की उचित मात्रा प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रित दरों पर बांटी जा रही है। मिट्टी का तेल आमतौर पर उचित दरों की दुकानों पर उपलब्ध रहता है यद्यपि कभी कभार किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए इसकी प्राप्ति भायद न रही हो और खाना पकाने वाली गैस की बिक्री का प्रबन्ध भिन्न भिन्न तेल की कम्पनियों द्वारा भाहरों की मांग को देखकर किया जाता है। यह कहना कि इन वस्तुओं की उपलब्धि एक स्वप्न बन गया है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को इनकी आव यकता है उन्हें यह बाजार में मिल रही है। प्रत्येक वस्तु की स्थिति निम्न प्रकार है:-

सीमेंट:-

राज्य की सीमेंट की त्रैमासिक आव यकता जिसका अनुमान अभी एक विशेष कमेटी ने राज्य में चल रही वि व बैंक की सहायता से योजनाओं तथा प्रगति मील कार्यों को मध्यनजर रखते हुए किया है, लगभग 2.90 लाख टन है। इसके विरुद्ध

27-2-1982 तक भारत सरकार हमें 1,41,400 टन सीमेंट प्रति तिमाही अलाट करती रहीं हैं। इसमें से लगभग 50 प्रति अत सीमेंट भारत सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में सिंचाई व बिजली योजनाओं के लिए सुरक्षित कर दिया रहा है तथा 10 प्रति अत उद्योगों के लिए। बाकी बचे 40 प्रति अत सीमेंट में से 47,000 टन सीमेंट प्रत्येक तिमाही से पब्लिक सेल कैटगरी के अन्तर्गत सुरक्षित रखी जाती थी और इसका वितरण जिला अधिकारियों द्वारा आम जनता में जिला स्तर पर किया जाता था। इसके पचात् जो भी सीमेंट बचेता था उसे सरकारी विभागों, सरकारी संस्थओं, बोर्डज, उद्योगों, नगरपालिकाओं / नगर सुधार मण्डलों तथा संस्थानों में बांट दिया जाता था।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, 27-2-1982 तक आम जनता की मांग को पूरा करने के लिए 47,000 टन सीमेंट की मात्रा प्रति तिमाही आरक्षित की जाती थी। इसकी जिलावार बांट प्रत्येक जिला की अबादी व निर्माण कार्यों को देखते हुए की जाती थी। ताहम सीमेंट की वास्तविक प्राप्ति एलौके अत के मुकाबले में लगभग 75 प्रति अत रही जिसके मुख्य कारण बिजली की कटौती, फ़ैक्ट्रीज का बन्द रहना मजूदरों में हड़ताल तथा यातायात की कठिनाई आदि हैं। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि जनता व सरकारी विभागों की सीमेंट की मांग केवल आंशिक रूप में ही पूरी हो सकी। राज्य सरकार का भरसक प्रयत्न रहा है कि वह सीमेंट एलौके अत को भारत सरकार से बढ़वाया जाए तथा

एलोके इन के विरुद्ध अधिक से अधिक मात्रा में सीमेंट की प्राप्ति हो तथा जो भी मात्रा प्राप्त हो उसका वितरण नियंत्रित माध्यमों से किया जाए। इन सभी कठिनाईयों के होते हुए भी हमारी उपलब्धि अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक अच्छी रही है।

जहां तक सीमेंट की बिक्री में चोर बाजारी कर संबंध है इस बारे में बताना चाहूंगा कि स्थानीय अमले द्वारा सीमेंट डीलरज के डिपूओं की लगातार चैकिंग की जाती रही हैं और इसके परिणाम स्वरूप 1-1-81 से 28-2-1982 तक 67 मुकदमें पुलिस में दर्ज करवाए गए और 1,03,417 रूपए की कीमत का सीमेंट पकड़ा गया।

28-2-1982 से भारत सरकार ने सीमेंट का आंशिक डी-कंट्रोल कर दिया है जिसके अनुसार सभी सीमेंट फैक्ट्रियों को कहा गया है कि वे अपनी इन्सटानड क्षमता का 66.6 प्रतिशत सीमेंट सरकार को लैवी सीमेंट के तौर पर बेचेगें। राज्य सरकार को पहले की भांति लैवी सीमेंट की एलोके इन निम्नलिखित वर्गों के उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए मिलती रहेगी:-

1. सरकारी विभागों, गैर सरकारी विभागों, निगमों तथा स्थानीय भासन कार्य

2. लघु औद्योगिक ईकाईयों को केवल उन के कारखानों की ईमारतों के निर्माण हेतु

3. सामाजिक सुधार योजनाओं, जैसाकि ग्रामीण आवास, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए आवास स्थान, हरिजनों, आदिवासियों तथा अन्य गरीब वर्गों के लोगों, ग्रामीण जल योजनाओं तथा दूसरे मदों को जो नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित हैं।

4. ऐसे रिहाय गी मकानों के लिए जिन की बुनियाद का क्षेत्र 80 वर्ग मीटर तक हो

5. रिहाय गी मकानों की मरम्मत के थोड़ी मात्रा।

राज्य की सिंचाई व बिजली योजनाओं के लिए सीमेंट की एलोके ान सीधी भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा लैवी सीमेंट सिनेमा, होटलों, ढाबों, बैंकों कई मंजिल की इमारतों, व्यापारिक संस्थानों ईमारतों तथा ऐसे रिहाय गी मकानों जिनका बुनियादी क्षेत्र 80 वर्ग मीटर से अधिक होगा, के लिए नहीं दिया जाएगा। तथा ऐसे औद्योगिक प्लाट्स को जो सीमेंट का प्रयोग कच्चे माल के तौर पर करतक है उन्हें भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी आव यकता खुले बाजार में बिक रहे नान लैवी सीमेंट से पूरी करनी होगी।

जैसे कि अच्छी तरह ज्ञात हैं सीमेंट की एलोके ान त्रैमासिक होती हैं। चूंकि सीमेंट की नई पालिसी 28-2-82 से लागू हुई हैं यानि कि तिमाही के मध्य से (जनवरी से मार्च) इसलिए भारत सरकार ने सीमेंट फैक्ट्रीज को निर्दे ा दिए हैं कि

इस तिमाही के बाकी के समय में पब्लिक सेल कटौगरी के अन्तर्गत अलाटकी गई सीमेंट की कुल मात्रा का केवल 1/10 भाग संबंधित राज्य को सप्लाई किया जाए। संक्षिप्त में हमारी कुल 47,000 टन की ऐलोके इन के विरुद्ध सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए यह बाध्य है कि मार्च, 1982 में वे 4,700 टन सीमेंट की मात्रा राज्य को सप्लाई करें। पब्लिक सेल कटौगरी में इतनी भारी कटौती करने का कारण सीमेंट कंट्रोलर द्वारा भेजे गए संदर्भों में अंकित नहीं हैं। इस कटौती से राज्य के पब्लिक सेल कोटा की उपलब्धि स्थिति काफी कठिन हो जाएगी। फिर भी जैसे ऊपर बताया गया है बहुत सारे खपतकार जैसाकि होटल, सिनेमा, महाजनी इमारतें इत्यादि जोकि आमतौर पर पब्लिक सेल कटौगरी में आती थी अब उन्हें इससे वंचित कर दिया गया है तथा पब्लिक सेल कटौगरी का लैवी सीमेंट अब केवल गरीब तबको तथा ऐसे रिहायशी मकान वालों को ही मिलेगा जिनकी बुनियाद का क्षेत्र 80 वर्ग मीटर तक होगा।

मुझे यह मानने में संकोच नहीं है कि इस समय नान लैवी सीमेंट की बिक्री 65 रूपए प्रति थैले के हिसाब से हो रही है। ताहम सीमेंट के आंशिक डी-कंट्रोल की नीति से सीमेंट फैक्ट्रीज को अपना उत्पादन बढ़ाने में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, चाहे उन्हें कुछ अधिक खर्चा भी करना पड़े। वे अपनी इन्सटान्ड क्षमता के 66.6 प्रतिशत सीमेंट से जो मात्रा अधिक उत्पादन होगी। उसे काफी अच्छे भावे पर बाजार में बेच सकेंगे। अनुमान लगाया जाता है कि इस से सीमेंट के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी जिसकी राष्ट्र

को निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत आवयकता हैं। बढा हुआ उत्पादन न केवल राष्ट्र के हित में होगा बल्कि इससे नान लेवी सीमेट की कीमतों में स्थिरता आएगी और यह जनता को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। यह सराहने योग्य हैं कि सीमेट के आंिक डी-कंट्रोल की नीति पहली बार देा में लागू की जा रही हैं। इसलिए दोनों प्रकार यानि कि लैवी तथा नान लैवी सीमेट के खुले तौर पर तथा समूचे तरीके से बिकने के लिए कुछ समय तो अवयक लगेगा।

मै सदन को विवास दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार स्थिति से पूर्णतय परिचित हैं। हम आम आदमियों तथा गरीब वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा करने के बहुत इच्छुक हैं। सीमेट उत्पादकों के साथ व्यक्तिगत तौर पर बैठके करके उन्हें इस बात पर बाध्य किया जा रहा हैं कि वे लैवी व नान लैवी सीमेट की अधिक मात्रा हरियाणा राज्य को अग्रता के आधार पर भेजे। एक मीटिंग पहले ही सीमेट नियंत्रक भारत सरकार से की जा चुकी हैं। जब भी आवयकता होगी हमें भारत सरकार से मामला उठाने में कोई संकोच नहीं होगा।

चीनी

भारत सरकार द्वारा नियंत्रित माध्यम से रूपए 3.65 प्रति किलो की दर से घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण हेतु हरियाणा राज्य को लैवी चीनी का 4,918 टन का मासिक कोटा अलाट किया

जाता है। प्रति व्यक्ति प्रति मास 400 ग्राम चीनी के हिसाब से हमारे वास्तविक मांग 5600 टन बनती है। हम भारत सरकार से अपने मासिक चीनी के कोटा में 700 की वृद्धि के लिए अनुरोध करते रहे हैं ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति को 400 ग्राम चीनी प्रति मास दे सकें। मगर भारत सरकार ने हमारे इस अनुरोध को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। राज्य सरकार ने इस आ आ में कि हमारी लैवी की चीनी की एलोके इन भीघ ही उन द्वारा बढ़ा दी जाएगी और कि प्रति व्यक्ति चीनी की मासिक मात्रा घटाने से भारत सरकार के साथ राज्य की चीनी की अतिरिक्त एलोके इन का मामला कमजोर होगा प्रति व्यक्ति प्रति मास 400 ग्राम का चीनी का कोटा नहीं घटाया। राज्य सरकार ने फिर से राज्य की चीनी की एलोके इन बढ़ाने हेतु उच्चतम स्तर पर मामला भारत सरकार से उठाया है और इसके अच्छे परिणाम निकालने की हमें आ आ है। भारत सरकार से लैवी चीनी की जो मात्रा प्राप्त होती है वह सभी जिलों में उनकी आबादी के आधार पर बांट दी जाती है। जिला प्र शासन जहां कहीं आव यकता हो चीनी के प्रति व्यक्ति कोटा में मकामी तौर पर परिवर्तन कर लेते है। हमारी सामान्य वितरण प्रणाली सारे राज्य में ठीक ढंग से चल रही है और इस बात का कोई प्र न ही उत्पन्न नहीं होता कि बहुत सारे गांवों को चीनी वितरण के लिए कई-2 महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर भी जब कोई डिपू कैंसल हो जाता है तो नया डिपू का प्रबन्ध करने के कुछ समय लग जाता है जिस के कारण छोटी मोटी कठिनाई अव य ही हो जाती है। यदि किसी मास में

चीनी के न आने के कारण या देर से आने के कारण इसका वितरण किसी स्थान पर नहीं हा पाता तो उपभोक्ताओं को आग्रामी मास में यह चीनी दे दी जाएगी।

लैवी चीनी का उपभोक्ताओं में वितरण 5320 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम (1280 भाहरी क्षेत्र में तथा 4040 ग्रामीण क्षेत्र में) से किया जा रहा हैं। उचित मूल्य की दुकानों के कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जाती हैं ताकि चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यावाही की जाए। भूगर कंट्रोल आर्डर की उल्लंघना करने के अपराध में जनवरी, 1981 से फरवरी, 1982 के समय के दौरान 30 मामले में पुलिस में दर्ज करवाए गए और 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया हैं। इन मामलों में रूपए 74,150 के भण्डार जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसी समय के दौरान 103 उचित मूल्य की दुकानों के लाईसैस रद्द किए गए तथा 574 डिपू होल्डरों की रूपए 1,67,401 की प्रतिभूति की राशि जप्त की गई।

मिट्टी का तेल

भारत सरकार द्वारा मिट्टी का तेल तदर्थ आधार पर अलाट किया जाता हैं। अक्टूबर 1980 से हरियाणा को प्रतिमास 8995 किलो लिटर मिट्टी का तेल अलाट किया जा रहा है जबकि इस से पहले यह लगभग 7000 किलो लिटर था।

इस समय मिट्टी के तेल की उपलब्धि स्थिति काफी संतोशजनक हैं यद्यपि इसे सुगम नहीं कहा जा सकता । फरवरी, 1982 के पहले पखवाड़े में बन्दरगाहों/तेल साफ करने वाले कारखानों से हिसार तथा अम्बाला में स्थित तेल कम्पनियों के डिपूओं पर मिट्टी के तेल में आने में रूकावट के कारण राज्य में इसकी कुछ कमी महसूस की गई थी मगर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार तथा आयल कम्पनीज के साथ तुरन्त मामला उठाए जाने के कारण इस की स्थिति में भीघ्र ही सुधार हो गया ।

मिट्टी के तेल का वितरण राशन कार्डों पर 5 लिटर प्रति कार्ड प्रति सप्ताह या 20 लिटर प्रति कार्ड मास की दर से किया जा रहा है । राज्य में मिट्टी के तेल की कमी नहीं है । जिला अधिकारी इसके ठीक वितरण के बारे पूरी निगरानी रख रहे हैं । 1-1-81 से 28-2-82 के समय के दौरान मिट्टी के तेल के विक्रेताओं के विरुद्ध 34 मामले पुलिस में दर्ज करवाए गए तथा 58 उन दोशियों जिन्होंने मिट्टी के तेल की बेच में हेराफेरी की के विरुद्ध विभागीय कार्यावाही की गई ।

जलाने वाली गैस:-

जलाने वाली गैस के वितरण पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हैं । गैस की सप्लाई भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार आयल कम्पनीज द्वारा स्वयं ही की जाती हैं ।

यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि राज्य सरकार वस्तुओं का उचित वितरण कराने हेतु कोई कसर नहीं छोड़ी और जहां तक संभव हो सका है इन वस्तुओं की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए उचित समय पर हर संभव पग उठाए है। इसके अतिरिक्त इनके वितरण में जो भी व्यक्ति अनियमितताएं करते पाए गए हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यावाही भी की गई है।

श्री अध्यक्ष: जिन्होंने काल अटैन्डान्स मोड में दिया था वे एक-एक सवाल पूछ सकते हैं।

चौधरी अजीत सिंह: स्पीकर साहब, चीनी के बारे में तो सुबह ही चर्चा काफी है मैं अब केवल सीमेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, ग्रामीण इलाकों में सीमेंट की बहुत ज्यादा किल्लत है। किसानों को अपने ट्यूबवैल्वज का कुछ काम कराने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है और जब भी उनको छोटी मोटी मरम्मत करनी होती है तो कई महीने तक उनको सीमेंट नहीं मिलता और ब्लैक में चाहे कितना ही सीमेंट ले लो।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि ब्लैक में तो सीमेंट मिलने का सवाल ही नहीं है। अब सीमेंट का पारिणियल डि-कन्ट्रोल हो गया है और 65 रूपए प्रति कट्टे के लगभग प्राइस फिक्स होने जा रही है। इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करके दो-तीन दिन के अन्दर पौलिसी बनाने जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनके मकान

का एरिया अस्सी गज है उनकी कन्ड्रोल रेट पर सीमेट दिया जाएगा और जो आदिवासी हैं या हरिजन हैं उनको भी मरम्मत के लिए सीमेट दिया जाएगा।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब से सीमेट की नई पोलिसी लागू हुई है स्टेट के अन्दर कितना सीमेट खुली मार्किट के लिए आया और कितना सीमेट लैवी का आया। अगर लैवी का सीमेट नहीं आया तो क्या स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया का लिखेगी कि लैवी का सीमेट मिलना चाहिए।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, सीमेट के बारे में पिछले महीने की 28 तारीख को फैसला हुआ है बहुत ज्यादा सीमेट लैवी का नहीं आया है। बहुत कम तादाद में आया है। जितना भी हमारा लैवी का सीमेट बनता होगा फ़ैक्टरी वाले उसको पूरा करेंगे। स्पीकर साहब, हमारे पास जो सीमेट आया है वह फ्री सेल का ज्यादा आया है।

चौधरी जया नारायण: स्पीकर साहब, भारत सरकार ने पोलिसी तय की है कि जा आदमी अस्सी गज में मकान बनाएगा उसको लैवी सीमेट दिया जाएगा। देहात के अन्दर तो इतने एरिया में मकान बनाया ही नहीं जा सकता। उन लोगों की तो मजबूरी होती है। उनको अनाज के लिए भी जगह चाहिए, पशुओं के लिए भी जगह चाहिए। क्या मंत्री महोदय, भारत सरकार के साथ

मीटिंग करके अस्सी गज के एरिया को दो सौ या अढाई सौ गज करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि 65 रुपए के हिसाब से चाहे जितना सीमेंट लें लें लेकिन कन्ट्रोल में दो चार कट्टे ही मिलते हैं। क्या सरकार ज्यादा से ज्यादा लैवी का सीमेंट लाने का प्रयत्न करेगी जिससे कि लोगों को अधिक सीमेंट कन्ट्रोल का मिल सके ? अध्यक्ष महोदय विधायकों को साठ हजार रुपया मकान बनाने के लिए लोन मंजूर हुआ है। बहुत से मकान अधूरे पड़े हैं क्योंकि सीमेंट नहीं मिलता क्या विधायकों को कन्ट्रोल रेट पर सीमेंट दिलवाया जाएगा?

श्री लछमन सिंह: जहां तक एरिया का संबंध है वह हमने तो किया नहीं है वह भारत सरकार ने किया है। एम0 एल0 एज0 को भी सीमेंट फ्री मार्किट से लेना पड़ता है।

(ii) आबकारी तथा कराधान मंत्री द्वारा राज्य में बंधक मजूदरों सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री महोदय, काल अटैन्डान्स मोशन नम्बर 44 के बारे में स्टेटमेंट देगे। अगर सदस्य सहमत हो तो स्टेटमेंट को पढ़ा हुआ समझा जाए।

कुछ आवाजें: नहीं जी। मंत्री महोदय को इसको पढ़ना चाहिए।

11.00 बजे

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):
स्पीकर साहब, राज्य के खादानों, ईंट के भट्टों, सड़क निर्माण व नहरों आदि पर कोई बन्धक मजूदर प्रथा नहीं है। इस संबंध में माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया है। यहां यह बताना उचित होगा कि बन्धुवा मुक्ति मोर्चा ने हरियाणा राज्य तथा अन्य के विरुद्ध वर्ष 1982 की जो रिट संख्या 1628 दाखिल की के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदे 1 दिनांक 5-3-1982 को दिये हैं:

“हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राज्य सरकार ने चौकसी कमेटियों का गठन किया है जिससे कि न्यायालय को वांछित परिणाम प्राप्त हुए.....।”

2. सही तथ्य इस प्रकार हैं कि बन्धुवा मुक्ति मोर्चा ने वर्ष 1982 की दो रिट क्रमांक संख्या 1628 व 2135 हरियाणा राज्य तथा अन्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की कि लाडवा जिला कुरुक्षेत्र स्थित लाला जगत राम वेद प्रका 1 तथा करनाल स्थित श्री ज्ञान चन्द दृचावला के इंटों के भट्टे व फरीदाबाद में मैसर्ज एस0 एल0 भार्मा एण्ड कम्पनी तथा अन्य की पत्थर की खादानों में बन्धक मजूदर कार्य करते है। वर्ष 1982 की रिट संख्या 1628 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार आदे 1 दिये है:-

“न्यायालय में दाखिल की गई 23 व्यक्तियों की सूची में से जिन 17 व्यक्तियों से न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग ने भेंट की, ने कहा कि वे अपने अपने घरों जिला मेरठ में जाना चाहते हैं। हरियाणा राज्य की ओर से पे 1 वाले विद्वान वकील श्री के0जी0 भगत ने कहा है कि उन व्यक्तियों को घर वापिस जाने बारे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह आदेश दिया जाता है कि इन व्यक्तियों को उनके प्रबन्धकों द्वारा न रोका जाए और उन्हें अपने अपने गांव को जाने दिया जाए। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि जिलाधी 1 मेरठ यथा संभव जहां वह मजूदर चाहें पुनर्वासित करे।”

3. वर्ष 1982 की रिट संख्या 2135 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं:—

“जिन मजूदरों के नाम रिट में दिये गये हैं और जिनकी रिपोर्ट आयुक्तों ने दी है तथा जिसका ब्यौरा अलग सूची द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया है उन्हें अपनी इच्छा अनुसार जहां वे चाहें जा सकेंगे और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा। यदि वे अपने गांव में जाते हैं तब वहां के जिलाधी 1 अपने अधिकार क्षेत्र के गांव में यथा संभव इनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगे।”

4. पहली रिट 2-4-82 तक स्थगित कर दी गई है और दूसरी रिट 19-4-1982 तक स्थगित कर दी गई है। जब कुछ

अन्य सूचना न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तुत की जानी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि श्रमिक बंधुवा हैं।

5.

राज्य में कुशल मजदूरों की कमी के कारण ईंट के भट्ठे आदि पर कार्य करने के लिये पड़ोसी राज्यों जैसे यू0 पी0, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से प्रवासी मजदूरों लाये जाते हैं। साधारणतः इन मजदूरों को भट्ठों और खादानों पर काम करने के लिये एडवांस राशि देकर लाया जाता है और यह राशि उनके वहां रहते रहते उनके वेतन में से काटी जाती है। राज्य सरकार ने इंटर-स्टेट माईग्रेट वर्कमैन (रैगुलेटिंग ऑफ इम्प्लायमेंट एण्ड कन्डीटिंग ऑफ सर्विस) एक्ट, 1979 के अन्तर्गत रूलज बनाकर प्रवासी मजदूरों की नौकरी की भातों को नियंत्रित करने के लिये 17-7-81 को उन्हें लागू किया जाए ताकि ठेकेदार तथा अन्य एजेंसियों उनका भोशण न कर सके। राज्य सरकार ने इस अधिनियम की परिपालना के लिए विभिन्न अथाकरिटीज की नियुक्ति की है। 199 ईंटों के भट्ठों के प्रबधकों ने पजीकरण के लिये तथा 75 ठेकेदारों ने लाईसैंस के लिये आवेदन पत्र दिये हैं। इनमें 108 पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रबधकों को जारी कर दिये गये हैं और भोश पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा लाईसैंस के लिये प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। डिसपनेसमेंट भता, आने जाने के किराया रहने के लिये घर, चिकित्सा सुविधाएं, पेय जल की सुविधाएं, बचाव के लिये कपड़ा और वेतन की अदायगी का

अधिनियम तथा रूलज में प्रावधान हैं। जहां तक राशन कार्ड का संबंध है प्रत्येक व्यक्ति अपना राशन कार्ड संबंधित खाद्य तथा आधिकारी से बनवा सकता है यदि वह उनके दफतर में प्रार्थना पत्र देता है।

6. बोडिन्ड लेबर सिस्टम (एबूलेशन) एक्ट, 1976 की परिपालना के लिये निम्न पग उठाये गये हैं:-

1. राज्य सरकार ने बोडिन्ड लेबर सिस्टम एक्ट, 1976 के अन्तर्गत जिलाधीशों को उनके अधिकार क्षेत्र में प्रयोग में आने वाली भाक्तियां प्रदान की गई हैं।

2. राज्य सरकार ने कार्यकारी न्यायाधीशों को राज्य में बोडिन्ड लेबर सिस्टम (एबूलेशन) एक्ट, 1976 की धारा 21 के अन्तर्गत अपराधों की खोज के लिये जुडिशियल मैजिस्ट्रेटस की भाक्तियां प्रदान की हैं।

3. प्रत्येक जिला तथा सब डिवीजनल के लिये चौकसी कमेटियों का गठन किया गया है।

जिलाधीश तथा सब डिवीजनल न्यायाधीश जो इन कमेटियों के अध्यक्ष हैं को कहा गया है कि वे इन कमेटियों में बैठके नियमित रूप से बुलाये और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को भेजे। ऐसी बैठके कई स्थानों पर पहले ही हो चुकी है।

7. राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, कोन्ट्रैक्ट लेबर (एबूले 1न) एक्ट, 1976 ईक्वल रैमेन्यूरे 1न एक्ट, 1976 एम्पलायमेंट आफ चिलड्रैन एक्ट तथा वर्कमैन कम्पनसे 1न एक्ट, 1923 की पूर्ण परिपालना के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

सरकार ने 36 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम वेतन निर्धारित/सं गोधन किए हैं। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 240 रूपये से लेकर 322 रूपये प्रतिमास तक है और इन्हें 1.50 पैसे प्रति बिन्दु की दर से मूल्य सूचकांक से जोड़ा हुआ है सिवाये 6 अनुसूचित रोजगारों को। यहां यह बता देना उचित होगा कि कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन 5 वर्ष की अवधि में सं गोधित किये जाने होते है। परन्तु हमारे राज्य की नीति अनुसार प्रत्येक दो वर्ष के प चात् आमतौर पर इनमें सं गोधन किया जाता है। इस नीति को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार सभी 36 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम वेतनों को सं गाशित करने के लिये भीघ्न कार्यवाही कर रही है। जिसके लिये 25.3.1982 को स्टेट मिनीमम वेजिज ऐडवाइजरी बोर्ड की बैठक बुलाई है।

इस अधिनियम की परिपालना के लिये क्षेत्रीय निरीक्षण स्टाफ को अधिसूचित कर दिया है और श्रम विभाग के श्रम तथा

समझौता अधिकारियों को कम वेतनों संबंधी क्लेमों को सुनने तथा फ़ैसला देने का अधिकार दिया गया है।

खेती बाड़ी में कार्यरत मजूदरों के हितों की रक्षा के लिये तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को भाक्तियां प्रदान की हुई है।

(2) कोन्ट्रैक्स लेबर (एबुले 11) एक्ट, 1976

इस अधिनियम की परिपालना के लिये रजिस्ट्रें 11/लाईसैंस अधिकारी नियुक्त किये हुये है। 108 प्रबन्धकों को पंजीकरण पत्र तथा 65 ठेकेदारों को लाईसैंस पहले ही जारी किये जा चुके है। क्षेत्रीय निरीक्षण अमले को इस अधिनियम की धारायों को लागू करने के लिये अधिसूचित किया हुआ है। राज्य स्तर पर इस अधिनियम को परिपालना के लिये स्टेट ऐडवाइजरी कोन्ट्रैक्स बोर्ड का गठन किया गया है। हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 9-7-1981 द्वारा टैस्सटाईल उद्योग व ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। कुछ अन्य उद्योगों जैसे रबड़, कैमीकल व डिस्टीलरी, ग्लास, पेपर कार्ड-बोर्ड में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना सरकार के विचारधीन हैं।

(3) इक्वल रैमेन्युरे 11 एक्ट, 1976

इस अधिनियम की धारायों की परिपालना के लिये दिनांक 18-1-1980 को क्षेत्रीय निरीक्षण अमले को अधिसूचित किया गया है। श्रम तथा समझौता अधिकारियों को इस अधिनियम

के अन्तर्गत उल्लंघनाओं तथा शिकायतों को सुनने के लिए तथा एक ही प्रकार के कार्य लिये पुरुशों तथा स्त्री मजूदरों को समान वेतन न देने बारे क्लेमों को निपटाने हेतु अथोरटीज के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

स्त्री मजूदरों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐडवाइजरी कमेटी का गठन किया हुआ है।

(4) इम्प्लायमेंट आफ चिल्ड्रन एक्ट, 1938

कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सामान्यतः पंजीकृत कारखानों में बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता अलबता कुछ अपने माता पिता के साथ जो भट्ठों तथा काटन जिनिंग कारखानों में काम करने आते हैं उनके साथ आ जाते हैं। कुछ ढाबों तथा छोटे होटलों में बच्चों के काम करने के उदाहारण हैं। क्षेत्रीय निरीक्षण स्टाफ को पहले ही कहा हुआ है कि वह दृढ़ता से कसूरवार प्रबन्धकों के विरुद्ध अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करें।

(5) वर्कमैन कम्पनसे लान एक्ट, 1923

राज्य सरकार ने पहले ही श्रम विभाग के श्रम तथा समझौता अधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत कमि नर नियुक्त किया हुआ है। ताकि वह मजूदरों को काम करते समय लगी चोट से संबन्धित क्लेम का फैसला कर सकें। वर्ष 1981 में ऐसे 350 क्लेम दाखिल किये गये जिन में से 180 क्लेमों का फैसला हुआ

और मजूदरों या उनके आश्रितों को मुआवजे के रूप में रुपये 6,01,230.25 दिलाये गये।

8. थामसन प्रैस एल्सन काटन मिलज फरीदाबाद के किसी मजूदर ने गैर कानूनी छंटनी बारे कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाया। अतः सरकार द्वारा उनके बहाल करवाने बारे कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

स्वामी अग्निवे : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च को मेरठ के 17 बुधआ मजूदरों को छुड़वाया और आदे 1 दिया कि इनको रिहैबलीटेड किया जाए तो ये किस तरह से कहते हैं कि राज्य में कोई बधुआ मजूदर नहीं हैं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बन्धुआ मजूदर करार नहीं दिया है।

स्वामी अग्निवे : अगर बन्धुआ मजदूर करार नहीं दिया है तो यह कैसे कह दिया है कि उनको रिलीज किया जाए और रिहैबलीटेड किया जाए। ऐसा तो बन्धुआ मजदूरों के लिए ही आर्डर होता है। (गोर)

मुख्य मंत्री: (चौधरी भजनलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय चाहूंगा ताकि स्वामी जी को और हाउस को पता लग जाए कि बन्धुआ लेबर के मायने क्या होते हैं। स्वामी जी के पास एक ही काम रह गया है कि किसी तरह से स्टेट का वातावरण खराब किया जाए, इनको और कोई काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अगर खेत में कोई किसान भी सीरी रखता है। तो उसको भी पहले पैसा देकर रखता है.....

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी मुख्य मंत्री जी ने फर्माया कि स्वामी जी को सिवाए स्टेट का वातावरण खराब करने के और कोई काम नहीं है। (गोर) इनको कोई अधिकार नहीं है यह बात कहने का कि स्वामी जी स्टेट का वातावरण खराब करते है। मेरी गुजारि । यह है कि इस पूंजीपति सोसायटी के अन्दर जब जब बन्धुआ मजदूर का सवाल उठा है तब तब पूंजीपति लोगों ने यही नारा दिया है। (गोर) जब कोई मजदूर हड़ताल की बात करता है तो ये कहते है कि यह स्टेट का वातावरण खराब करता है। (गोर)

चौधरी भजनलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था हरियाणा प्रान्त में बन्धुआ लेबर बिल्कुल नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है। अगर किसी कि वह बन्धुआ मजदूर को कोई हाई कोर्ट का जज भट्टे वाले की कस्टडी से छुड़वाता तब तो मान लेते कि वह बन्धुआ मजदूर था। अध्यक्ष महोदय, किसान भी जब खेती में सीरी रखता है तो उस को पहले पैसा देना पड़ता है। इसी तरह से भट्टे पर भी जब मजदूरों को लाया जाता है तो उनको पैसा देना पड़ता है। ताकि उस गरीब को यह तसल्ली हो जाए कि उसका पैसा नहीं मरेगा। इसमें मजदूर की सेफटी है। मजदूर भट्टे वाले के पैसे भी मार कर भाग सकता है। मैं इस बारे में बहुत सी मिसालें भी दे सकता हूं कि

इसमें मजदूर की सेफटी है। आज तक कहीं से पंचायत नहीं आई कि फलां जगह बन्धुआ मजदूर है। स्वामी जी का तो यह काम है कि पांच आदमी कहीं से पकड़ लिये और लाकर खाड़े कर दिये। वे कहते हैं कि भट्ठे वाले के हमारी तरफ पैसे हैं और वह हमें जाने नहीं देता। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेट में अगर भट्ठा इंडस्ट्री फेल हो गई तो सारी डिवैल्पमेंट के काम रुक जाएंगे। मैं स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी बातें न करें। अगर किसी का कोई पैसा मार लेता है तो कल को कौन खेतों में काम करेगा कौन भट्ठों पर काम करेगा और कौन खानों में काम करेगा? हरियाणा सरकार की गरीब मजदूरों के साथ पूरी हमदर्दी है। हम हरियाणा में गरीबों के साथ ज्यादाती नहीं होने देंगे।

चौधरी अजीत सिंह: स्पीकर साहब, मेरे हल्के बेरी के अन्दर एक क्राइमर से 24 बन्धुआ मजदूरों को रिहा करवाया गया है। वह क्राइमर एक कांग्रेस के नेता का है और उसने बेरी हल्के से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस कांग्रेस के नेता पर गांव की पंचायत ने दो हजार रुपए जुर्माना भी किया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन मजदूरों में से किसी आदमी को जेल में रखा गया और क्या यह बात सही है। कि उस नेता पर गांव की पंचायत ने दो हजार रुपए का जुर्माना किया ? क्या ये सारी बातें मंत्री जी के नोटिस में हैं।

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं है। (गोर)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब मैं विभिन्न कार्यों के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नियत किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूँ।

“The Committee met at 11.30 A.M. on Tuesday, the 30th March, 1982 in the Chamber of the Hon’ble Speaker.

The Committee after some discussion recommended that the business on the 31st March, 1st April and 2nd April, 1982 be transacted by the Sabha as follows:--

Wednesday, the 31st March, 1982 (9.30A.M.)

1. Question Hour.
2. Presentation and adoption of the Third Report of the Business Advisory Committee.
3. Motion under Rule 30.
4. Appropriation Bill in respect of Budget.
5. Appropriation Bill in respect of Excess Demands for Grants over Appropriation.

Thursday, the 1st April, 1982 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

Legislative Business

(1) The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill 1982 (alongwith notice of disapproval of the ordinance given notice of by Shri. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)

(2) The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill 1982 (alongwith notice of disapproval of the ordinance given notice of by Shri. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)

(3) The Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1982.

(4) The Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, 1982.

(5) The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1982.

3. Discussion on the report of Shri. Baldev Tayal Committee (Notices given by Chaudhri Khurshid Ahmed, Minister and Sarvshri Ajit Singh, Ram Singh Mann, Jagdish Kumar Baniwal).

Friday, the 2nd April, 1982 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Motion under Rule 15.

3. Motion under Rule 16.

4. **Legislative Business**

(1) The East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 1982.

(2) The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1982.

(3) The Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, 1982.

(4) The Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, 1982.

(5) The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1982.

5. Official Resolution regarding Estate Duty in respect of agricultural land in the Haryana State.

6. Discussion on motion under Rule 84.

(1) That the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulation, 1981, be taken into consideration and discussed.

(2) That the 6th Annual Report and Accounts for the year 1979-80 of the Haryana Seeds and Development Corporation Limited be taken into consideration and discussed.

(3) That the Annual Audit Report of the Haryana Agricultural University, Hissar for the year 1979-80 be taken into consideration and discussed.

(4) That the Annual Financial Statement for the year 1981-82 and received Estimates (Budget Estimates) for the year 1980-8-1 of the Haryana Electricity Board be taken into consideration and discussed.

(5) That the Annual Statement of Accounts for the year 1977-78 of the Haryana State Electricity Board be taken into consideration and discussed.

(6) That the Administration Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1978-79 be taken into consideration and discussed.

(7) That the Statement showing the loan raised by the Haryana State Electricity Board upto 31-1-1982 for which the State Government have stood guarantee for repayment thereof be taken into consideration and discussed.

Shri. Mool Chand Jain and Dr. Mangal Sein stressed that the House should meet on 5th April, 1982 to complete the pending business but this was not agreed to by the majority of the Members of the Committee.”

वित्त मंत्री (चौधरी खुरीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की तृतीय रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की तृतीय रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को स्वीकार करता है।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): स्पीकर साहब, जो मैंने आज हाउस में पेश किया है मैं इसका विरोध करने के लिए

खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, यह बहुत ही एक्सट्रा आडिनरी सिचुएन है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आम तौर पर रूलिंग पार्टी के सदस्य और मुखतलिफ विरोधी पार्टियों के लीडर इकट्ठे होते हैं। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में डिस्कान के बाद सर्वसम्पति में हुए फैसले की रिपोर्ट आती है। लेकिन यह पहली मर्तबा है कि रूलिंग पार्टी अपनी ब्रूट मैजोरिटी की वजह से ऐसा कर रही है। क्योंकि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में भी रूलिंग पार्टी की मैजोरिटी है, इसलिए उस रिपोर्ट की हाउस से ये एप्रूवल लेना चाहते हैं। स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग 23 मार्च को हुई थी और उस मीटिंग की रिपोर्ट हाउस ने 23 मार्च को एप्रूव कर दी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार हाउस का एजेन्डा 2 अप्रैल तक के लिए फिक्स हो चुका था। लेकिन 22 मार्च की मीटिंग के बाद कुछ और मोन आई है। जैसे मुझे पता लगा है कि एस्टेट ड्यूटी का रैजोल्यूशन हाउस के एजेन्डे पर लाना चाहते हैं क्योंकि 22 मार्च की बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हमारे सामने इस बारे में कोई जिक्र नहीं आया था। इसके अलावा श्री बलदेव तायल द्वारा दी गई वन मैन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का भी 22 तारीख की मीटिंग में जिक्र नहीं था। इसके अलावा 7 मोन और आई है। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि दो दिन के सेशन में इतना बिजनैस कैसे समाप्त हो सकता है? हमने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी अफेवर्ज मिनिस्टर से कहा कि

आप हाउस को बढ़ा दें। हमने यह भी कहा कि यदि आप 5 अप्रैल को सैशन नहीं करना चाहते तो 6,7,8 या 9 तारीख को सैशन कर लें। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 8 अप्रैल को प्रधान मंत्री जी आ रही हैं। इसलिए 8 अप्रैल को सैशन नहीं हो सकता। उस समय मैंने कहा कि यदि आप 8 अप्रैल को नहीं कर सकते तो उससे अगले दिन कर लें। स्पीकर साहब, लोक सभा और राज्य सभा का जब सैशन होता है तो वे भी कई बार चलते हुए सैशन के दौरान अपनी सीटिंग कई कई दिन के लिए एडजर्ट कर देते हैं। इसके बाद हमने यह भी कहा कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह भी कहा कि 2 अप्रैल को राम जी का त्यौहार है इसलिए उस दिन सैशन नहीं होना चाहिए लेकिन उस समय यह प्रेसीडेड दिखया गया कि पहले कि जिस दिन रामनोमी थी उस दिन भी सैशन हुआ है। स्पीकर साहब, पेपर्ज में इस बात की खबर आई है कि लोकसभा में भी रामनौमी को सैशन होने के बारे में चर्चा हुई है। उस बारे में लोकसभा के पालियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने यह कि यदि अपोजीशन के सदस्य यह कहते हैं कि रामनौमी को लोकसभा का सैशन नहीं होना चाहिए तो सैशन नहीं होगा। स्पीकर साहब, लोकसभा में भी कांग्रेस की रूलिंग पार्टी है और हरियाणा में भी कांग्रेस की रूलिंग पार्टी है लेकिन यह नकली कांग्रेस पार्टी है। (गोर)

स्पीकर साहब, कुछ बिजनैस उस समय हमारे सामने नहीं था जिस समय दूसरी मीटिंग हुई थी। प्रिवीलिज कमेटी की

रिपोर्ट आ गई थी और वह उसके चेयरमैन ने वापस ले ली। उस पर आपने कहा था कि किसी भी चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट रोकने का अधिकार नहीं है। यदि चेयरमैन के दिल में ऐसी कोई बात होती तो रिपोर्ट को रोकने से पहले चेयरमैन को अपनी कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी और सारे मैम्बरों से सलाह करके ही कोई आगामी कार्यवाही करनी चाहिए थीं। इन हालात में जबकि रूलिंग पार्टी मैजोरिटी में हैं और हम लोग माइनोरिटी में हैं इसलिए आपको सही बात माननी चाहिए। इस 90 सदस्यों के हाउस में हम 40 अपोजी उन के सदस्य हैं। यदि हम अपनी कोई रीजनेबल बात भी न मनवा सके तो फिर इससे ज्यादा और क्या दुःख की बात होगी। इन लोगों ने अपनी ब्रूट मैजोरिटी का फायदा उठाया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: जैन साहब ब्रूट मैजोरिटी का मतलब क्या होता है?

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, ब्रूट मैजोरिटी का यही मतलब है कि माइनोरिटी की कोई बात मैजोरिटी ग्रुप न माने। (गोर) और वह अपनी मनमानी करके काम चलाये। (गोर) स्पीकर साहब, इनकी ब्रूट मैजोरिटी है और ये मनमानी से काम करना चाहते हैं इसलिये हमारे पास सिवाए गांधी जी के रास्ते पर चलने के और कोई रास्ता नहीं है। (गोर) यदि ये इस तरह की बातों को भी नहीं मानेंगे तो यह हाउस कभी नहीं चलेगा। With all the sincerity and with all the emphasis at my command. I

warn the Government कि इन हालात में हमारे लिए गांधी जी के बताए हुए रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। (गोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजनलाल): अध्यक्ष महोदय, अभी बाबू मूलचन्द जैन जी ने मैजोरिटी की बात की हैं और एक बात गांधीवाद की कहीं है। (गोर)

चौधरी भजनलाल: स्पीकर साहब, 2 तारीख तक का फैसला बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में हो चुका था। सारी बातें उस समय हमारे सामने थी। सिवाए एक रैजोल्यूशन के। इन्होंने एक बात और कही थी कि यह पार्टी नकली पार्टी है। (गोर) मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि हमारी नकली पार्टी है। तो आपकी क्या पार्टी हैं। नकली पार्टी तो आपकी हैं। जिस समय चरण सिंह जी आए उस समय आपको स्टेज पर भी नहीं चढ़ने दिया। (गोर) जितने सदस्य आपके हैं ये आपकी कोई एक बात भी मान कर दिखा दें तो मैं मान जाऊँ। (गोर) हाउस में आपके सदस्य आपकी एक बात भी नहीं मान रहे। (गोर) नकली पार्टी आपकी है। जब आपको स्टेज पर नहीं जाने दिया था तो उसी समय आपको अस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते तब मालूम होता कि आप असली पार्टी के नेता है। (गोर)

श्री मूल चन्द जैन: समय बतायेगा कि मैं असली लीडर हूँ या नहीं। जिस समय में राजनीति के अन्दर आया था उस समय तो आप बच्चे ही थे। (गोर)

चौधरी भजनलाल: मैं आपकी इज्जत करता हूँ। (गोर)

श्री अध्यक्ष: मैं आप सब साहेबवान से एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एप्रोप्रिए इन बिल 30 तारीख के लिए रखा था क्योंकि इस बिल पर 31 तारीख को गर्वनर साहब के हस्ताक्षर होने हैं and then only the finances of the State will start functioning. मैंने सभी मैम्बरान को हर विशय पर बोलने के लिए ज्यादा समय दिया है। डिमांडज पर बोलने के लिए एक दिन से समय बढ़ा कर दो दिन का समय दिया। आज 31 तारीख हैं। मैं हाउस की कार्यवाही थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यह जो एप्रोप्रिए इन बिल है यह पास होकर प्रैस में प्रिंट होने के लिए जायेगा। और वहां से आने के बाद आज रात के 12.00 बजे से पहले पहले इस पर गर्वनर साहब के हस्ताक्षर होने हैं This I have forced on the Government in order to give more time for discussion on demands.

इस लिये मेरी यह डियूटी हैं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। As far as the other thing is concerned. I only wish to say that मैंने एक सिंटिंग नहीं बढ़ाई बल्कि चार सिंटिंग हैं। एक भानिवार को एक 29 तारीख को 11.00 बजे से लेकर 6.00 बजे तक नौन स्टोप और दो सिंटिंग एक और दो तारीख की बढ़वाई है। अभी बाबू जी ने कहा हैं कि दो चीजे ज्यादा आई है। रूल 84 के अधीन ये चीजें बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में आ सकती है।

श्री मूल चन्द जैन: क्या अब इसमें चेन्ज हो गयी हैं?

श्री अध्यक्ष: जहां तक तायल साहब की रिपोर्ट का सम्बन्ध है उस के लिए सिर्फ आधा घन्टा डिस्क इन एलाउड है। एक और रैजोल्यूशन जो एस्टेट डियूटी के सम्बन्ध में गर्वनमेंट की तरफ से आया है उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसमें यही है कि एस्टेट डियूटी के लिए जमींदारों की जमीन की लिमिट 50 हजार रूपये की बजाये डेढ़ लाख रूपये हो जायेगी। इससे तो सभी सहमत होंगे। (गोर)

श्री सुरेन्द्र सिंह: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, इस हाउस में जब कभी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पें आ होती है तो उस पर अपोजीशन के मैम्बर बोल लेते हैं, उनको बोलने का टाईम दे दिया जाता है। जब आपस में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कशन होती है तो लीडर आफ दि हाउस उसका जवाब दे देते हैं या अपनी बात कह लेते हैं। यदि यही देखना है कि इस में कुछ नहीं होता तो बात अलग है। लीडर आफ दि हाउस का जवाब आने के बाद आप अपनी रूलिंग दे देते हैं। यदि काम मैजोरिटी की वजह से करना है तो सारा काम एक घंटे में ही खत्म हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो बिलज है या दूसरे विशय हैं इन पर एक्सपर्ट्स से सलाह लेनी होती है। इन पर सभी मैम्बरों ने बोलना होता है। इसलिये दो तारीख की बजाये सैशन 5 तारीख का रख लिया जाये। हमारे सामने इतना काम है कि यदि सैशन

प्रातः 9.00 बजे भुरु किया जाये तो रात 10.00 बजे तक भी पूरा नहीं हो सकता । (गोर)

स्पीकर साहब, मेरी गुजारि । यह है कि जल्दी क्या हैं? दो और तीन तारीख को अगर सै न न करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो दिन बाद सै न कर लें। (विधान) स्पीकर साहब, मैं तो अपने लीडर वैसे सिर्फ यही विनती करूंगा कि 2 तारीख को इतनी देर तक बिजनैस चलाने की बजाये अगर ये उसे किसी दूसरे दिन टेक आप करवा लें तो ठीक रहेगा।

डा० मंगल जैन (रोहतक): स्पीकर साहब, बाबू मूलचन्द जैन जी ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही कही है। मुझे बड़ा खेद है कि मुख्य मंत्री जी ने उनको एपोरि एट नहीं किया। स्पीकर साहब, आपने एक बात फरमाई है कि 30 तारीख को एप्रोप्रो एन बिल आना था। लेकिन आपके बड़े दबाव देने के बाद ये इसे 31 तारीख को लाने के लिए माने। स्पीकर साहब, 15 तारीख को सै न भुरु हुआ है। इनकी ओरिजिनल प्लान के मुताबिक यह 31 मार्च तक चलना था। स्पीकर साहब, इनको किसने रोका था कि ये सै न को 8 मार्च से न बुलाये? और गर्वनर साहब की स्वीकृति इतनी जरूरी है भी तो इनको एक सप्ताह पहले सै न बुलाने से किसने रोका था? पता नहीं ये किस मामले में म गूल रहे।(विधान) भायद टिकटो के चक्कर में घूमते रहें हो। खैर मैं तो यह कहूंगा कि अगर सै न का समय न बढ़ा तो हमारे साथ बड़ी ज्यादाती होगी। जब बिल्ज इतने थे

रूल 84 के तहत हमने पहले से ही डिस्कान नौन कंट्रोलियल हैं हो सकता वह इनीमेंट रैजोन्यू इन कंप्लीके इन का रूप धारण कर जाए क्योंकि इस समय वह हमारे सामने नहीं हैं। केवल उनका चहेरा देख कर हम तो स्पीकर साहब, मेरा कहना है कि आपको इनके साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिये। आपकी हमदर्दी तो हमारे साथ होनी चाहिए क्योंकि होम वर्क हमने करना है सारी किताबें हमने पढ़नी हैं। इनके पास तो स्टाफ है। इनको वह बता देगा कि यहां यहां अन्डरलाईन किया हुआ है राठी साहब को उर्दू में लिखकर वे पढ़ावा देगे। (विधान) स्पीकर साहब, प्रिवलेज कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में आने से जिस तरह से रोका गया है वह अनहर्ड आफ है। सुनने में आया है कि स्वामी जी की तरफ से ऐसी एप्लीके इन आई हैं कि एक ही कास्ट के 8 लोगो थे इसलिये न्याय नहीं हुआ। अगर यह बात सही है तो बड़ी लज्जा की बात है। (विधान) ऐसा इल्जाम रूलिंग पार्टी के लोगो की तरफ से भी आया है आज भी स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि श्री सुरेन्द्र सिंह को पी0 यू0 सी0 से इसलिये ड्रौप किया गया, उन्हें विद्वान करने के लिए इसीलिये मजबूर किया गया क्योंकि वे इसके इतारे पर नाचने के लिये तैयार नहीं थे वे अपनी जमीर के मुताबिक चलना चाहते थे (विधान) स्पीकर साहब, बाबू जी के ब्रूट मैजोरिटी का भाब्द इस्तेमाल करने पर आपने पूछा कि ब्रूट मैजोरिटी की डैफिनि इन क्या है? स्पीकर साहब, जहां रीजनेबलनैस न रहे हैं। जहां पर दलील सुनने के लिये कोई तैयार न हो, उसको ब्रूट मैजोरिटी कहते है चाहे वह एक वोट से

ही क्यों न हो। ठीक हैं इनके पास चेपे हुये आदमी है जैसा मर्जी चाहें ये कर लें। (विघन) तो स्पीकर साहब, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह फ़ैग एन्ड आफ दि टर्म है। इसमें हमें अनप्लैजैन्टनैस लेकर नहीं जाना चाहिए। इनको दो दिन और सै ान बढ़ाने के लिए इनके ही नौजवान उदयमान नेता ने सुझाव दिया है। हमारी नहीं तो ये उनकी बात ही मान लें क्योंकि इनको आखिर में उनकी भारण में ही जाना पड़ेगा। (विघन) तो स्पीकर साहब, मैं बड़े पुरजार भाब्दों में आपके द्वारा इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जेसा बाबू मूलचन्द जैन जी ने कहा ये हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिय मजबूर न करे और यहां कोई अनप्लैजैन्ट बात न हो। (विघन) इन्हें चाहिए कि ये हमारी बात को मान कर पांच तारीख को भी सै ान कर लें और प्रिवलेज कमेटी की रिपोर्ट जो प्रिन्ट हो चुकी है, वह हाउस में आ जाए और उस पर डिसक ान हो जाए। भजनलाल जी आप स्वी आदित्यवे ा को आखिर कब तक बचाओगे? (विघन)

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, इसका बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने हैं इसको वापिस लिया जाना चाहिए। बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दुबारा बुलाई जानी चाहिए। और 5 तथा 6 तारीख को सै ान होना चाहिए। इसी में सबकी भान है।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि.....

.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर आधे घण्टे से ज्यादा डिसक इन नहीं हो सकती।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, किसी को तो पन्द्रह मिनट मिल गए हैं और किसी को दो मिनट भी नहीं मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, इस पर डिसक इन होते आधे घण्टे से ज्यादा समय हो गया है।

श्री बलदेव तायल (हंसी): स्पीकर साहब, प्रजातंत्र के अन्दर अपोजी इन का रोल बहुत अहम होता है। अपोजी इन की सिर्फ इतनी डिमांड है कि बिजनैस को देखते हुए इस से इन को थोड़ा बड़ा दिया जाए। एक दिन या दो दिन के लिए जितनी बिजनैस डिमांड करता है यह वैसे बड़ा दिया जाए। मेरी समझ से बाहर बात है कि रूलिंग पार्टी की ऐसी क्या तकलीफ दिखाई दे रही है। जो यह हमारी इस मांग को मानने के तैयार नहीं है।

एक आवाज: यह बात आपको बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में उठानी चाहिए थी।

श्री बलदेव तायल: मीटिंग के अन्दर सुन लेते और हमारी बात मान लेते तो यह बात कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जब वहां पर हमारी बात नहीं सुनी और न ही मानी तभी यहां

पर कहना जरूरी है। आप भी इस विषय में सोचिए। ऐसा करने से इनकी कितनी तारीफ होगी और इनका बडप्पन भी है। अपोजी इन की मांग हैं कि हाउस के सामने काफी बिजनैस है। सी0एम0 साहब ने कहा कि हम स्टेट का खर्चा बनवाना चाहते हैं। अगर स्टेट का ही पैसा बचाना है तो एमरजेन्सी के पट्रैन पर चलते हुए अप्रैन्वली भंग कर दो। कौन्सिल आफ मिनिस्टर्ज का 24 का काफिला बैठा रखा है क्या इस पर आपका पैसा खर्च नहीं होता है? क्या असैम्बली को ही चलाने में पैसा खर्च होता है? आप छोटी सी कैबेनिट क्यों नहीं बनाते? इसनक लोगों को कार्पोरेट इन के चेयरमैन और दूसरी चीजों पर खर्च कर रह है इसे क्यों नहीं बचाते ? (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह आखिरी सै इन है। पता नहीं इस सै इन के बाद हाउस में कितने मैम्बर्ज आयेगे। एक बात कहना चाहता हूं कि आठ तारीख को प्रधानमंत्री तारीफ ला रही है। मुं ख्य मंत्री जी ने भी यह फरमाया है कि सै इन फिर बुला लेंगे। आठ तारीख के बाद कोई भी सै इन की तारीख रख लें। आप किसी भी तरह कर लें। दो चार दिन के बाद या आठ तारीख के बाद सै इन बुला लें।

वित्त मंत्री (चौधरी खुरीद अहमद): स्पीकर साहब, इस हाउस के सामने जितना बिजनैस है उसे देखते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसी के अनुसार यह कह गया है कि दो तारीख तक हाउस चलेगा लेकिन फिर

दोबारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। पहली रिपोर्ट में एडजस्टमेंट करने के बाद उसे हाउस में रखा गया है। उसमें दोबारा कोई ज्यादा चेंज नहीं हुई है। कोई भी नयी बात नहीं आयी ओर न ही हाउस से सामने इतना लम्बा चौड़ा बिजनेस है कि सारी ही रिपोर्ट इस काम के कारण बदल दें। ऐसी बातों के लिये सै इन को आगे चलाना ठीक नहीं। कोई ऐसी इन्टैस्ट वाली बात नहीं है। श्री बलदेव तायल जी कह रहे थे कि खर्चा कम करना चाहिए।

श्री बलदेव तायल: मैंने यह नहीं कहा। सी० एम० साहब ने कहा था।

चौधरी खुर शिद अहमद: अगर आपने यह नहीं कहा तो चलो मैं अमौड कर देता हूँ कि सेविंग करनी है। (ओर एवं व्यवधान) लीडर आफ दि हाउस को डा० मंगल सेन ने कहा कि इनकी ब्रूट मैजोरिटी है इस वजह से रिपोर्ट एडाप्ट करवा लेंगे। जनाब किसी अपोजी इन की माइनोरिटी इस कदर होपलैस हो जाये उसमें फ्रस्ट्रे इन आ जाये तो हम क्या करें? (ओर एवं व्यवधान) मैं समझता हूँ तमाम बातें हाउस में आ चुकी हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सारों बातों को अच्छी तरह से कन्सिडर किया है। कोई भी जस्टीफिके इन हाउस को बढ़ाने की नहीं बनती है। हाउस का टाईम दो तारीख तक के लिए फिक्स किया है। इसलिये मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को पास करे।

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि यह सदन कार्य सलाहाकार समिति की तृतीय रिपोर्ट मे दी गई सिफारि गों स्वीकार करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बगैर जो भी मैम्बर बोलेगा। उसे रिवार्ड न किया जाये। (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप हमारी एक बार बात तो सुनिये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपोजी इन के साथियों को मै ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट करता हूं। रूलज द्वारा अलाऊ पर भी एकोमोडेट करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं मानता हूं कि आप हमें एकोमोडेट करते है। आपने चार दिन का सै इन भी बढ़वा दिया लेकिन आज हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादाती हो रही है। मैं प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के बारे मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन को एक (aggrieved member, who ever may be) ने एप्लीके इन दी कि मैं कुछ और सबूत देना चाहता हूं इसलिये मुझे फिर मौका दिया जाये। इस बात पर आपने अलाऊ कर दिया कि अगर वह नये सबूत देना चाहता है तो दे। मैं यह कहता हूं

कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट(गोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं उस बात के बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस एप्लीकेशन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई और न ही हाउस को बताया गई। यह फ्रैंच एवीडेन्स कहां से और कब आ गई? सवाल तो यह है कि उसे पूरा मौका एवीडेन्स का दिया गया या नहीं ? (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी खुरीद अहमद: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। जो बात श्री वीरेन्द्र जी ने कही हैं उस बारे में कोई आइटम एजेन्डे में हाउस के सामने नहीं है। चेयर की इजाजत के बगैर ही किसी बात को डिस्कस करना ठीक नहीं। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि बिना एजेन्डे के किसी आइटम पर डिस्कशन की जाय। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जहां तक पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के इलैक्शन का सम्बन्ध है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के बारे में मेरे पास श्री सन्त कंवर ने लिख कर दिया है कि श्री हीरा नन्द आर्य और श्री रण सिंह मान आउट आफ स्टेटेमेंट हैं इसलिये उनके नाम उन्हें वापिस करने की परमिशन दी जाये। I would not be happy in their withdrawing their names but I can only permit that if the whole House unaninmously agrees to that. (Interruptions)

श्री मूल चन्द जैन: यह कैसे हो सकता है जो मैम्बर यहां हाजिर नहीं हैं उनके बारे में कोई आदमी इस बात को कैसे कर सकता है।

श्री अध्यक्ष: इसी लिए तो मैंने हाउस से पूछा है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री मूलचन्द जैन: विधि अनुसार यह बिल्कुल नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: आपकी ही पार्टी के जनरल सैक्रेटरी हैं। उन्होंने लिखकर दिया है वरना मैं उनका नाम वापिस करने में इन्ट्रैस्टिड नहीं हूँ। जब तक यूनानीमसली हाउस न माने और उनके सिगनेचर न हो कि हम अपना नाम वापिस लेना चाहते हैं तब तक नाम वापिस हो सकते। पी० ए० सी० और एस्टीमेन्टस कमेटी का इलैक्शन होगा।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि रूलज आफ प्रोसीजर कंडक्ट आफ बिजनेस के रूल 30 को सस्पैन्ड किया जाये और 1 अप्रैल, 1982 को गवर्नमैट बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाये।

12.00 बजे

वित्त मंत्री (चौधरी खुरीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाये तथा वीरवार 1 अप्रैल, 1982 को सरकारी कार्य किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनेस के रूल 30 को सस्पैन्ड किया जाये तथा वीरवार, 1 अप्रैल, 1982 को सरकारी कार्य किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि हरियाणा विधानसभा के रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनेस के रूल 30 को सस्पैन्ड किया जाये तथा वीरवार, 1 अप्रैल, 1982 को सरकारी कार्य किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Mr. Speaker: I have another announcement to make and that is क्योंकि आज पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के लिये इलैक्शन के लिये काफी देर हो गयी है। इसलिये I would request the House to agree to have the election tomorrow.

Voices: Yes

श्री जय नारायण वर्मा: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर महोदय ने अपनी बात को कहते हुए और गवर्नमेंट को डिफैट करते हुए एक बात कही। उन्होंने यह कहा कि सारी अपोजी इन होपनलैस हो चुकी हैं और फ्रस्ट्रेटिड है। (व्यवधान व भाोर)

उन्होंने यह कहा कि अपोजी इन होपलैस और फ्रस्ट्रेटिड हो चुकी है। यह डैमोक्रेटिक से कहते हैं कि यह फ्रस्ट्रेटिड है I do not take notice of that. (व्यवधान व भाोर)

बिल्ज—

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिए इन (नं० ३) बिल, 1982

श्री अध्यक्ष: अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब हरियाणा एप्रोप्रिए इन (नं० ३) बिल पे टा करेगें।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर शीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं हरियाणा विनियोग (सं० ३) विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा विनियोग (सं० ३) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा विनियोग (सं० 3) विधयेक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर।(व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुन लें ह। अगर आप हमारी बात पूरी सुन ले तो भायद वह बात होने से बच जाये जो होने जा रही हैं। आज सरकार इन्ट्रैस्टिड नहीं है कि हम यहां पर बैठे। ये जान बझूकर ऐसा सीन किएट करना चाहते हैं (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज ही मैम्बरों ने एक सवाल हाउस में उठाया जिसके बारे में चेयर की तरफ से भी आया कि उस एग्रोव्ड मैम्बर ने प्रिविलेज कमेटी को एक फ्रै । दरखास्त दी हैं कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। क्योकि इस कमेटी मै एक पर्टीकुलर कास्ट के मैम्बर है। आपने स्पीकर साहब यह फरमाया है कि उस एप्लीके ।न को कमेटी को रैफर कर दिया है मेरा कहना यह कि कमेटी चूकि इस हाउस का ही हिस्सा हैं वह दरखास्त हाउस के सामने लायी जाये। यहां उस को डिस्कस करने का मौका दिया जाये। वह दरखास्त जिसमें मैम्बर ने यह कहा कि मेरे पास कुछ फ्रै । एवीडैन्सिज हैं और आपने जो अनाउन्समैट की हैं कि वह दरखास्त कमेटी को भेज दी हैं वह दरखास्त हाउस में आनी चाहिये। मै आपसे यह गुजारि । करना चाहता हूं कि इसकी वजह से कई किस्म के भाक सुबह लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं । इसलिये मेरा कहना यह

है कि उसे हाउस में लाया जाना चाहिये ताकि उस का मैम्बरज डिस्कस कर सके। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: जहां तक मेरी पहली अनाउसमेंट का संबंध हैं मेरे पास एक दरखास्त आनरेबल मैम्बर से आयी। मैने उस को प्रिविलेज को फावर्ड कर दिया अगर रूल्ज के मुताबिक वह एप्लीके इन हाउस में पे ा की जा सकती हैं तो मै रूल्ज को चैक करके उस एप्लीके इन को हाउस के अन्दर रख दूंगा। अगर रूल्ज के अन्दर कोई ऐसा प्रॉवीजनल नही होगा कि यह एप्लीके इन को हाउस के अन्दर नहीं आ सकती होगी तो ऐसा नहीं हो सकेगा। 90 मैम्बरज में से अगर कोई भी मैम्बर मुझे कोई एप्लीके इन देता है तो मुझे उसको रूल्ज के अनुसार ही डील करना पड़ेगा। अगर रूल्ज में ऐसा प्रोवीजनल होगा कि वह हाउस में पे ा की जा सकती हैं तो वह हाउस के अन्दर पे ा कर दूंगा। वरना कमेटी उसकी एग्जामिन करेगी।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब मैं भी प्रिविलेज कमेटी का मैम्बर हूँ। प्रिविलेज कमेटी में जो भी मैम्बरज होते हैं वे स्पीकर साहब आप द्वारा नौमिनेट होते हैं उस कमेटी के लिये इलैक् इन नहीं होता। इसलिये मैं स्पीकर साहब आपसे यह दरखास्त करूंगा कि अगर आपको कोई एप्लीके इन ऐसी मिलती हैं जिसमें यह अलैज किया जाता हैं कि एक ही कौम के 8 आदमी है तो क्योकि यह कमेटी आप द्वारा नौमिनेट की हुई होती हैं इसलिये यह आपके ऊपर भी एसप िन हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा

कि ऐसी एप्लीके इन को तो कमेटी को फावर्ड करने के कोई जरूरत नहीं हैं। आप उसको सुओ-मोटो डिस्मिस कर सकते हैं और डिकलाईन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बात कही हैं उसके संबंध में मैं यह कहता हूँ कि 90 के 90 मैम्बर्ज

are honourable , respectable and gentlemen. जो 9 या 10 मैम्बर्ज मैंने प्रिविलेज कमेटी में नोमीनेट किये थे I will be the last person to accept any reflection on their integrity. on their fairness and on their impartiality. I will never indulge in it. I can never tolerate that anybody may doubt on anybody's fairness, impartiality and integrity. (Noise and interruptions). 90 के 90 मैम्बर्ज की इम्पा र्शियलिटी फेयरनेस और इन्टैग्रिटी के बारे में कोई बात हो मैं टोलरेट नहीं कर सकता। खास कर 10 मैम्बर्ज के बारे में जिनको मैंने नोमीनेट किया था। उनकी इम्पा र्शियलिटी इन्टैग्रिटी ओर फेयरनेस पर किसी किस्म का कीचड़ उछाला जाये यह मैं कतई तौर पर टोजरेट नहीं कर सकता।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, मैं भी इस सन्दर्भ में एक दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस किस्म से प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट होल्ड बैक या रि काल की गयी हैं उस तरह से नहीं की जानी चाहिए and especially on the behest of the Chairman alone, the Report should not have been

returned. जो चेयरमैन हो वह जब इस बात में इन्ट्रैस्टिड हो कि वह रिपोर्ट हाउस में नहीं आनी चाहिए..... (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: अगर इन्डैस्टिड नहीं था तो उसने पहले साईन करके क्यों दी थी।

श्री बलदेव तायल: कई बार ऐसा होता है कि जब किसी कमेटी की रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है तो..... (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: I have just said that I will not tolerate anything against any hon. Member (interruptions) चेयरमैन की इन्टैग्रिटी के बारे में कोई बात नहीं हो सकती।

Shri. Baldev Tayal: Sir, I am not taking about anybody's integrity, (interruptions& noise).

श्री अध्यक्ष: अब मैं हाउस से यह रिक्वैस्ट करता हूं कि हम थोड़ा सा काम कर लें। उसके बाद गप भाप कर लेंगे। (Interruptions and NOise) अगर कोई मैम्बर साहब एप्रोप्रिए इन बिल पर डिस्क इन करना चाहता हूं तो कर ले।

(At this stage on hon'ble Member rose to speak).

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि हरियाणा एप्रोप्रिए इन (सं० ३) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर कलाज बाई कलाज विचार करेगा।

कलाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि कलाज 3 का बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गीद अहमद): स्पीकर साहब मैं
प्रस्ताव करता हैं—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० २) बिल, १९८२

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० २) बिल प्रस्तुत करता हूँ।

मैं भी प्रस्ताव करता हूँ कि:—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० २) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० २) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

(जब ये बिल पास हो रहे थे तो विरोधी दल की ओर से लगातार भाोर तथा नारेबाजी हो रही थी।)

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० २) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर कजाज बाई कलाज विचार करेगा।

कलाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कलाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गिद अहमद): स्पीकर साहब में
प्रस्ताव करता हैं—

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(इस समय भी विरोधी पक्ष की ओरसे लगातार नारेबाजी तथा भाोर हो रहा था।)

Mr. Speaker: I would request the hon'ble Member that let the Appropriation Bill be passed first as it has to be passed and presented to the Governor today.

(iii) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल, 1982

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल प्रस्तुत करता हूँ।

मैं भी प्रस्ताव करता हूँ कि:—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्जाज बाई कलाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गीद अहमद): स्पीकर साहब मैं
प्रस्ताव करता हैं—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

12.15 बजे

(तत्प चात सदन वीरवार, 1 अप्रैल, 1982, प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)

ANNEXURE

Non-Directory Villages in the State

705. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) whether there are any non-directory village, having separate abadis, which are not being considered as revenue estates independently, in the State; if so, tehsil-wise names thereof; and

(b) whether the Government has received any representation that non-directory villages, as referred to in part(a) above existing in Panipat tehsil, be converted into directory villages; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House together with the action, if any, taken thereon?

Revenue Minister (Sh. Phool Chand):

(a) Yes Sir, The names of such villages, tehsil wise are indicated in the list Annexure 'X'.

(b) Yes Sir, Copy of the representation in question is added at Annexure 'Y'. The matter is still under consideration of the Government.

ANNEXURE - X

List of Non-Directory Villages

District Ambala

Tehsil Naraingarh	
1	Abupur
2	Taprian
3	Bhood Majra
4	Rampur
5	Chamel Majra
6	Balti
7	Barail Majra
8	Bhal-Majra
9	Yashin Majra
10	Jahoor Maijri
11	Jaintipur
12	Mandoa
13	Mirpur
14	Dakra
15	Ratta Tibbi
16	Mhadon
17	Pinjan Wala
18	Rana

19	Bhula Khari
20	Jheri Wala
21	Tarkan Wala
22	Bhud Farozeli
Tehsil Ambala	
1	Basantpura
2	Taprian
3	Majri
4	Rampur
5	Balapur
6	Jodhpur
7	Kathgarh
8	Durga Nagar
9	Chhotighel
10	Ram Dass Nagar
11	Rattangarh
12	Keshopur
13	Baraham Majra
14	Haripur

Tehsil Kalka	
1	Bharalli Town
2	Alipur Town
3	Sontawala
4	Khera
5	Tindan
6	Kalaniwala Bas
7	Khala Wala Bas
8	Laban Kheri Wala Bas
9	Laban Kheri Jaggarwala Bas
10	Puns Wala Bas
11	Mitosar Bunwala Bas
12	Pritosar Bunwala Bas
13	Shivni Mandir Dera
14	Tibbi Wala Bas
15	Tada Wala Lanana
16	Gujarwala Bas
17	chhoti Moli Wala Bas
18	Tadan Wala Bas

19	Tandan Wala
20	Kharanpur Tprian Wala
21	Sukhi Majra
22	Girdhra Wala
23	Dali Wala
24	NOhar
25	Lehi Upparli
26	Majri Sita Ram Wali
27	Naggal Babu Singh Wala
28	Gudam
29	Pipli Ghati Bair Chati
30	Dora
31	Bas Sardara
32	Gujjaran Wala
33	Labni Wala
34	Jiddan
35	thamar
36	Dera Wala
37	Gujjrar Ka Bas

38	Khuda
39	Sainaih Ka Bas
40	Chandi Kotla
41	Maha Devi Wali
42	Ghati Wala
43	Sukhri
44	Surajpur Factory
45	Rattpur Colony
46	vishavkaram Colony
47	Amwala Wala
48	Jaggar Wala
49	Nurbu Wala
50	Masjid Wala
51	Piran Wala
52	johri Wala
53	Kute Wala
54	Mugni Wala
55	Ambka
56	Ishwar Nagar

57	Virat Nagar
58	Majri Labana
59	Majri Gujran
60	Majri Harijan
61	Khera Harijan
62	Khera Brahamanana
63	Abadi Girdawar
64	Abadi Harijanan
65	Bara Nichla
66	Bara Upprala
67	Jai Singh Pura
68	Mattan Wala
69	Kishangarh
70	Bel Wali
71	Bahar
72	Rurkri
73	Murad Naga
74	Shampur
75	Kandai Wala

76	Laskri Wala
77	Bhud Daraiki
78	Morni
79	Turan
80	Baldadwala
81	Jolly
82	Mohli Wala
83	Sher Jwainki
84	baloti
85	Madhan Dhani Ram
86	Madhan Shish Ram
87	KHet Parali Plasra
88	Pudh Garh
Tehsil Jagadhri	
1	Jai Pura
2	Nagla
3	Isharpur
4	Taprian Gadholi
5	taprian Harijanan

6	Misri Ka Majra
7	BIch Ka Majra
8	Bagh Ka Majra
9	Buria Kit Taprian
10	Taprian
11	Sekhpura
12	Taprian
13	Taprian
14	prit Nagar
15	prit Nagar
16	Phush Garh
17	Mandebri Ka Majra
18	Pir Majra
19	Mansapur
20	Maharpur
21	Kaiamgarh
22	Shadipur
23	Taprapur
24	Model Town

25	Akalgarh Ka Majra
26	Kesri Ka Majra
27	Kishanpura
28	Nandpura
29	Kansli
30	Khera
31	Kinki Taprian
32	Harijan Majiri
33	Harijan Taprian
34	Bali Majra
Tehsil Chhachhrauli	
1	Chikan Muslmanan Gujjar
2	Gisar Pari
3	Majiri Harjananar
4	Kot Musalmanan
5	Majra
6	Mahmood Bas
7	Banjara Bas
8	Faizpur

9	Tiwari
10	umbli
11	Bas Upparla
12	Chandpur
13	Barham Majra
14	Majri Tappu
15	Chakki Ki Abadi
16	Ram Bara
17	Madauli Gujjar Uprli
18	Madauli Gujjar Darmiani Majra
19	Madauli Gujjar Malha
20	Bali Majra
21	Maunda
22	Begampur Majra
23	Jleh
24	Rangar Majri
25	Sekhu Pura
26	Banaman Pur
27	Dalip Garh

28	Kher Bas
29	Sampolia Bas
30	Dran Wala
31	Kubipur
32	Harijan Majri
33	Halndpur
34	Dadipur
35	Garon
36	Sina
37	Desori
38	Bhanngeri
39	Bhagpat
DISTRICT KURUKSHETRA	
Tehsil Guhla	
1	Karvee Gamria
2	Harijan Gamri
3	Plot Majbi and Bajigar
4	Plot Labana Chd.
5	Purbia Plot

6	Labana Plot
7	Bhagalpur Plot
8	Bajigira Plots
9	Kishore Colony
10	Bajigra Plots
11	Zeranpur plot
12	Dera Bhag Singh
13	Plot Bajigira
14	Rai Singh Plot
15	Bagal Plot
16	Amritsar Plot
17	Bajigar plots
18	Oesha Singh Wala plot
19	Labana plot
20	plot Jesha Singh wala
21	Plot Nanda
22	Bajigar Wala Plot
23	Dahra Singh Plots
24	Bajigar Plot

25	Harijans plot
26	Bajigar Wala
27	Premput
28	Nihang Wala
29	Gamri
30	Khera Swala
31	Brari Plot
Kaithal Tehsil	
1	Labana Plots
2	Devi Garh
3	Neembwala
4	Tehparlad
5	Dara Gurdasspura
6	Sihli Khera
7	Jil Garh
8	Kohoi Wala
Thanesar Tehsil	
1	Suntokh Pura
2	Ramnagar

3	kundanpura
4	Sanpura
5	Jagania
6	Anu Wala
7	Surajgarh
8	Dera Such Singh
9	Duppura
10	Gamri
11	Nibwala
12	Dera Bajigira
13	Babha Gram
14	Bishan GARh
15	Santinagar
16	Candigarm
17	Abadibhantha
18	Abadibajigira
19	Model Town
20	Majri
21	Derapurbian

DISTRICT KARNAL	
Tehsil Assandh	
1	Naya Jindha
2	Dera Gama
3	Dera PHoola Singh
4	Padhana
5	Manchoori
6	Pinghala
7	Pucca Khera
8	Rangruti Khera
9	Manpura
Tehsil Karnal	
1	Bharatpur
2	Mangal Garhi
3	Manakpura
4	Nanakpura
5	Devipur
6	Jhimar Garhi
7	Garhi bhalar

8	Gobind Garh
9	Amupur Majra
10	Abdulapur
11	Rattak Garh
12	Purbian Deara (Kachwa)
13	Skiligar Dera (Barsat)
14	Biani (biana)
Tehsil Panipat	
1	Garhi Nawab
2	Ram Nagar
3	Jeet Garh
4	Harijan Colony (Kawi)
5	Singhpura
6	Garhi Kewal
7	Garhi Tagan
8	Garhi Veshak
9	Nagla
10	Pathar Garh Navada
11	Khera

12	Garhi Simla
13	Jeet Garh Ram nagar
14	Rajapur Doosri Abadi
15	Basti Jogian
16	Simbal Garhi
17	Gosian Wala
18	Jeet Garh (Jorasi Saraf Khas)
19	Bhilchpari
20	Noorwala
21	Ramra
District Sonapat	
Tehsil Sonapat	
1	Garhi Keshri
2	Garhi Lala
3	Garhi
4	Garhi Chhoti
5	Garhi Jhajhara
6	Garhi Kalan
7	Garhi Ghulama

8	Bethni
9	Garhi Rajlu
10	Rattan Garh
11	Naya Khanda
12	Chhota Khanda
13	Nai Basodi
14	Garhi Asadpur
15	Garhi Tikola
16	Garhi Memarpur
17	Garhi Jajal
18	Jagdishpur
19	Tanda
Gohana Tehsil	
1	Hudda Gangana
2	Hassangarh
3	Wazipura
4	Sani Pura
5	Garhi Near Kheri Damkan
6	Naya Busana

7	Chhaniar
DISTRICT GURGAON	
Tehsil Ferozpur Jhirka	
1	Kalakhera
2	Kolarhera
3	Kaliawas
4	Madanivas
5	Fauladavas
6	Gowarasi
7	Manyawas
8	Nabuwas
9	Navalgarh
10	Pioroli
11	Khera
12	Mora
13	Khalenta
14	Parparwas
Tehsil Gurgaon	
1	Chand Nagar

2	Khera
3	Dhani Ramji Lal Wali
4	Dhani Sunderpur
5	Dhani Siwari
6	Dhani Mechana
7	Jora Khurd
8	Chainpura
9	Dhani Kumbawas
10	Dhani Chitarsain
11	Dhani Saimuwali
12	Nangal
13	Preem Nagar
14	Bhim Nagar Khera
15	Dhani Harjian
16	Dhani Malyan
17	Dhani Chamaran
18	Gairak Khera
19	Amar Singh Wali Dhani
20	Dhani Rajawali

21	Khera
22	Ramgarh
23	Bamroli
24	Rampura
25	Dhani Sohan Wali
26	Dhani Molar Wali
27	Naya Gaon
28	Dhani Shankar Wali
Tehsil Nuh	
1	Pipaka
2	Pataka
3	Ghu Baitik
4	Kirari
5	Bhatlaka
6	Nai Nangla
7	Dhani Malyan
8	Dhani Dhobian
9	Gaurakpur
10	Gudah

11	Dhillaki
12	Mewali Kabas
13	Ranika
14	Bhuraka
15	Machhroli
16	Othaka
17	Bhargaka
18	Gudwas
19	Mahraka
20	Khabgarh
21	Chaban
DISTRICT ROHTAK	
Tehsil Jhajjar	
1	Abadi Bawarian
2	Bahargarh
3	Azad Nagar
4	Surajgarh
5	Rampura
6	Khajpur

7	Naya Gaon
8	Agarpur
9	Ghatauli
10	Mangawas
11	Dhani Kutani
Tehsil Kosli	
1	Dhani Ahiran
2	Dhani Jatan
3	Bas
4	Bhagwanpura
5	Ramgarh
Tehsil Rohtak	
1	Garhi Bohar
2	Asthal Bohar
3	Garhi Majra
4	Jindran
5	Gudhan
Tehsil Meham	
1	Indegarh

2	Ganga Nagar
3	IMli Garh
4	Kishanpura
DISTRICT SIRSA	
Tehsil Sirsa	
1	Dhani Sainpal
2	Dhani Mani Singh Wali
3	Dhani MUKhtyar Singh Wali
4	Dhani Partap Singh Wali
5	Dhani Jugian
6	Dhani Charson Wali
7	Dhani Bilas Par Wali
8	Dhani Sheran
9	Dhani Kaluwali
10	Dhani Purbian
11	Dhani Majra
12	Dhani Muthar
13	Dhani Bhanguwali
14	Dhani Partap Singh Wali

15	Dhani Nigrana There
16	Dhani Faqiran Wali There
17	Dhani Narain Singh There
18	Dhani Ram Pur Thari
19	Dhani Mohar Singh Thar
20	Dhani Samanmder Singh Theri
21	Dhani Asa Singh
22	Dhani Ratta Khera
23	Dhani Rasup Pur Thari
24	Dhani Swarn Singh
25	Dhani Khajan Singh
26	Dhani Noujukhera
27	Dhani Rampur
28	Dhani Kalu Ram
29	Dhani Kehar Singh
30	Dhani Lakhbir Singh
31	Dhani Farwahin
32	Dhani Bajigar Wali
33	Dhani Kum Thal

34	Dhani Harijanane
35	Dhani Kirpal Singh
36	Dhani Dabbar
37	Dhani nana lal wali
38	Dhani Iswar Singh
39	Dhani Bauta Singh Wali
40	Dhani Iswar Singh
41	Dhani Maujal Ther
42	Dhani Saidan Wali
43	Dhani Buta Singh Wali
44	Dhani Sangat Pura
Tehsil Dabawali	
1	Dhani Raj Pura
DISTRICT MOHINDERGARH	
Tehsil Rewari	
1	Dhani jarawar
2	Dhani Chamar Was
3	Dhani Ahiran
4	Hari Nagar (Hussian Pur)

5	Hazari Was
6	Nangla Dolatpur
7	Dhani Ghisa wali
8	Bhim Nagar
9	Dhani Gujaraan Wali
10	Dhani Had
11	Dhanora
12	Kund Mandi
13	Dhani Sobha
14	Hari Nagar (Dharuhera)
Tehsil Bawal	
1	Khatiwas
2	Dhani Ahiran (Bawal)
3	Dhani Ahiran (Dharan)
4	Dhani Jaitpur
5	Dhani
Tehsil Mahendragarh	
1	Dhani Mandhiwali
2	Dhani (jarwa)

3	Dhani Bhalothia
4	Dhani Nangla
5	Dhani Kumharan
6	Dhani Jawahar Nagar
7	Akoda
8	Dhani (Akoda)
9	Dhani Inderewali
10	Dhani Rajputan
11	Dhani Shyamian
12	Dhani Bas
13	Dhani Maliyan
14	Dhani sheopura
15	Dhani Khatiwali
16	Dhani Mandhiwali
17	Dhani Harijan Wali
18	Dhani Kanwali Wali
19	Dhani (Chajiwasi)
20	Dhani Bohra Wali
21	Dhani Jatan

22	Dhani (Zedpur)
23	Dhani jhakhri
24	Dhani Jeetawali
25	Dhani Hemraj Wali
26	Dhani Shadiwali
27	Dhani Tekawali
28	Dhani Inderwali
29	Dhani Gandhi Nagar
30	Dhani Kharkhara
31	Dhani Bas
32	Dhani Shyamia Wali
33	Dhani (karira)
34	Dhani Gusian Wali
35	Dhani (Ishran)
36	Dhani Ahiran Wali
37	Dhani Kumbran Wali
38	Dhani
Tehsil Narnaul	
1	Dhani Bas

2	Dhani Ahiran
3	Dhani (Kirarod)
4	Dhani Maliyan
5	Dhani Jatan
6	Guga Wali Dhani
7	Mamraj Wali Dhani
8	Bhaggu Wali Dhani
9	Dhani Maliyan
10	Dhani Asawali
11	Dhani (Dokhera)
12	Dhani Doewali
13	Dhani Rawatan
14	Dhani Laxman Wali
15	Dhani Tihagian
16	Dhani Prema Wali
17	Dhani Gujrawali
18	Dhani thakrawali
19	Dhani Neelpur
20	Dhani Jadma

21	Dhani Bataran
22	Khem chand Wali
23	Chhaju Ram Wali
24	Dhani Jatan
25	Dhani Chhapra
26	Dhani Poswat
27	Dhani Kankarwali
28	Dhani Khamawali
29	Dhani Barwali
30	Dhani Chhimawali
31	Dhani Barandia Wali
32	Dhani Moolawali
33	Dhani Ahiran Wali
34	Dhani Sangawali
35	Dhani Mojiawali
36	Dhani Dakore
37	Dhani Gularwali
38	Dhani Brahman Wali
39	Dhani KOthawali

40	Dhani Sadwali
41	Dhani Sadhwali
42	Dhani Khariawali
43	Dhani Buja Pichhli
44	Dhani Gopasadhki
45	Dhani Ramdeva Wali
46	Dhani Nawada Wali
47	Dhani Maliyan Wali
48	Dhani JOkhla Wali
49	Dhani Neemla Wali
50	Dhani Khariawali
51	Dhani Chuha Wali
52	Dhani bandwali
53	Dhani bayawali
54	Dhani Bakhtawali
55	Dhani Shyamiawali (Sirahi babali)
56	Dhani Khatia Wali
57	Dhani Shyamia Wali

	(Bhangarka)
58	Dhani Bania Wali
59	Dhani Kumbhawali
DISTRICT JIND	
Tehsil JInd	
1	Sirsa Kheri
2	Karamgarh
3	Khera Ramrai
4	Dhani
5	Sundurpur
6	Khurda
Tehsil Safidon	
1	Baniya Khera
2	Rajana Khurd
Tehsil Narwana	
1	Narwalgarh
2	Rattanpura
BHIWANI DISTRICT	
Tehsil Bhiwani	

1	Dhani Harsukh
2	Gobindpura
3	Halwas
4	Dhirana Kanlan
5	Dhani Biran
6	Keharpura
7	chainpura
8	haripura
9	Golpura
10	Patharwali
11	Lehlana
12	Sundawas
13	Bilanabas
14	Lachhmanpura
15	Dhani Dhana
16	Kherpura
17	Dhani Amin Lal
18	Dhani Rewasa
Tehsil Dabri	

1	Dhani Khubi
2	Tilori
3	Dhani Lakha Singh
4	Dhani Kushalwali
5	Dhani Bedesra
6	Dhani Gudana Ahiran
7	Dhani chhanwali
8	Panaml Pilan
9	Dhani
10	Dhani
11	Dhani
12	Kishanpura
13	Dhani Ishar
14	Dhani
15	Dhani Hirawali
16	Dhani Kehar Singh
17	Atela Kalan Naya
18	Colony Electricity Board
19	Ram Nagar

20	Nihalgarh
21	Dhani
22	Dhani Maliyan
23	Arya Nagar
24	Dhani
25	Dhani Ganeshi
Tehsil Loharu	
1	Dhani Ganga Bishan
2	Dhani Samaspur
3	Dhani Toda
4	Jagram Bas
5	Sukhdev Singh Ka Bas
6	Bas
7	Dhani INdraj
8	Dhani Lalpur
9	Dhaniawali Dhani
10	Dhani Bhagasra
11	Naya Bardu
12	Dhani Rathiyan

13	Dhani Malian
14	Rambas
Tehsil Bawanikhere	
1	Sukhpura
2	Dhani Jatan
3	Dhani Rangran
4	Alakpura
5	Kehri Daulatpur
6	Milak Pur
7	Dhani Kesla
8	Jlta Kheri
9	Durjan Pur
10	Sikandarpur
11	Chortapur
12	Dhani Khusal
13	Dhani Kirawar
Tehsil Siwani	
1	Dhani Balara
2	Dhani Hunat

3	Dhani Bhirja
4	Devsar
5	Dhani Kishan Lal
6	Dhani Dariya Pur
7	Garanpura Khurd
8	Dhani Miran
9	Jainawas
10	Sherpura
11	Sainiwas
12	Motipura
13	Bas
14	Dhani Ketwar
15	Dhani Behal
DISTRICT HISAR	
Tehsil Hisar	
1	Dhani mangali Mohbat
2	Hari Kot
3	Barsa
4	Sikarpur

5	Dhani Raipur
6	Kishan Garh
7	Kheri
8	Kandul
9	Faridpur
10	Kinala
11	Dhani Garan
12	Dhani Khan bahadur
13	Dhani Prem Nagar
15	Migalpura
16	Shankerpura
17	Madanpura
18	Kundanpura
Tehsil Tohana	
1	Dhani Modawali
2	Dhani ladhuwali
3	Dhani Lehratheh
4	Dhani Bilaspur
5	Dhani Bilaspur

6	Nanheri Khurd
7	Dhani Badanpur
8	Dhani Jogdan
9	Dhani Bajigar
10	Dhani Raji
11	Deshmesh Nagar
Tehsil Rattia	
1	Neemri
2	tameshpura
3	Zandwala sotar
4	Dhani Agam
5	Nurk Ali
6	Chugwali
7	KHomar
8	Dhani Bhutaram
9	gursuar
10	Dhani Raipur
11	Dhani Babanpur
12	Dhani Lamba

13	Dhani bilaspur
Tehsil Fatehbad	
1	Chanawali
2	Dhani bilaspur
3	Dhani Daryapur
4	Ratta Tibba
5	Ahilsadar
6	Naktia
7	Haripura
8	Banawali
9	Musawai
10	dhani Ishwar
11	Akanwali
12	Daulatpur
13	Dhani Ahrwan
14	Dhani Dhaka
15	Dhani Mamuram
16	Karya
17	Salamkhera

18	Chebalmori
19	Bahaanwali
20	Dhani Khasa
21	Dhani binja Lamba
22	Chanda Chock
23	matana
24	Dhani Dhoba
25	Masitawali
26	Tahilwali
27	Dhani Majra
28	Rampura Dhani Bahal Bhawanria
Tehsil Hansi	
1	Dhani Brhmnan
2	Garhi Azima
3	Dhani Kumharan
4	Garhi
5	Dhana Khurd
6	Dhani Pirwali

7	Kundanpura
8	Richpura
9	Dhani Piran
10	Dhani Kumharan
11	Rampura
12	Jitpura
13	Lalpura
14	Dhani Kendar
15	Dhani Chakarpur
16	dhani Sobha
17	Bara Suleman
18	Sainipura
19	Dhani Manekhan
20	Dhani Paul
21	Dhani Raju
22	Dhani Shankeria
23	Dhani Gujran
24	Dhani Thakri
25	Dhani Puria

26	Bara jagga
27	Dhani Bukhari
28	Dharampura
List of Dhanis/Majras in District Faridabad	
Sr. No.	Name of Dhani/Majra
DISTRICT FARIDABAD	
Tehsil Ballabgarh	
1	Lakhmi Wali
2	Mewla Wali
3	Fatehpur Wali
4	balbir Wali
5	balkar Singh Wali
6	Kabal Singh Wali
7	Dhig Ram Wali
8	Ram Saran Wali
9	Jagir Singh Wali
10	Bhup Nagar Wali
11	Saperi Wali
12	Chapli Jhuggi

13	Bahadur Singh Wali
14	bhatpura
Tehsil Hathin	
1	Kumarhera
2	Mithaka
3	Chilli
4	Malpuri
5	Mathepur
6	huchpuri Khurd
7	huchpur Kalan
8	Chila Wali
9	Nauragangabad
Tehsil Palwal	
1	Nagla Sati
2	Nagla jheparwas
3	Inayat Pur
4	Mohammad Pur
5	Noragbad
6	Kan pur

7	Pitappa
8	Pirgarhi
9	Hafzabad
10	Bharatgarh
11	Attar Chatta
12	Nagla Sheru
13	Achhega
14	Hahabad
15	Bhawana
16	Karimpur
17	Nai Nagla
18	Charyan ka
19	Amir Pur
20	Nagla Sapla Wala
21	Nanda Wala
22	Kamre Wali
23	Aya nagar
24	Kanijro Ka Nagla (Badrau)
25	Kanjro Ka Nagla (Sondha)

26	Berah Patti
27	Garhi Patti
28	Sebh Shalir
29	Salla Garh
30	Islama bad
31	Shamshbad
32	Lakhi Singh Ka Nagla
33	Kashipur
34	Munir Garhi
35	Gopalgarh
36	Shri Nagar
37	Saraj
38	Ahsaan Pur
39	Nakhrola
40	Ajijabad
41	Aligarh
42	Bawalya ka

ANNEXURE-Y

“Mool Chand Jain

D.O. NO. LOP-81/

Dated 15-10-1981.

Dear Shri Caprihan,

This is regarding conversion of long standing village habitatiins into directory villages.

2. There are a number of good sized village habitation some existing for the last 40-50 years or even more. These habitations have their separate names and are recognised as such by the Postal Department as well as the Election Department as in the electoral rolls the voters of such habitations are entered under their own names. Such habitations arenot directory villages and hence these have not their separate jamabandis etc. as they are not separate revenue estates. They also do not enjoy other facilities given to directory villages. But many ot them were recognised as separate villages during the consolidation proceedings with their own ‘Phirni’ and their abadis. At least such habitations should be converted into directory villages.

3. In my constituency of Panipat Tashil such habitations are:- Kewal Garhi (now included in Village Jaurasi), Simal Garh (now included in village Rakasera), Ajit Garh (situated between village Jaurasi and Atta), Ramra (perhaps included in village Tamsabad) and a few other habitations included in village kundla. The main disadvantage at present to such habitations is that they are not provided with separate link roads and sometimes even electricity.

4. I studied the provisions of the Land Revenue Act and I found that you, as Financial Commissioner, are competent to declare such habitations as revenue estates and after that they will be called as directory villages. Public interest demands that all these habitations should be declared as directory villages. I am interested not only in such habitations situated in my constituency but all over the State. Therefore, I suggest that a report should be had from all the Collectors and then some guidelines be formulated to declare these habitations as revenue estates and hence directory villages.

With regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(Mool Chand Jain)

Shri P.P. Caprihan IAS,
Financial Commissioner, Revenue,
Haryana.